



चीन की 'रोबोट सेना' ने बनाया... पेज 5



एक महीने तक बिहार के राजगीर में... पेज 7

मुकाबले के चक्कर में आदमी का जीवन एक कारखाने के समान हो गया है, आदमी का सबसे विश्वसनीय अवतार

वर्ष 6, अंक 340

भोपाल, शुक्रवार 22 मई, 2026

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, षष्ठी पश्चात सप्तमी 2083

मूल्य 2 रूपए



मेलोडी से आगे... पीएम मोदी के खास तोहफों ने जीता दुनिया का दिल

दैनिक कारखाने का सफर।
एजेंसी नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni को दी गई 'मेलोडी' टॉफी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन इसके साथ पीएम मोदी उनके लिए भारत की दो खास सीमाओं भी लेकर गए। इनमें असम की मूंगा सिल्क से बनी सुनहरी रेशम की साड़ी और मणिपुर के दुर्लभ शिरुई लिली फूल से प्रेरित सिल्क स्टोल शामिल है। अपनी 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने अलग-अलग देशों के नेताओं को भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े अनमोल उपहार भेंट किए।

FAO के डायरेक्टर जनरल को महाराष्ट्र के ऑर्गेनिक मिलेट्स बार दिए गए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री को सिकिकम के प्रेस फूलों की पेंटिंग, जबकि राजा हाराल्ड V को ओडिशा की तारकसी कला से बनी चांदी की सेलबोट भेंट की गई। स्वीडन के प्रधानमंत्री को मणिपुर की लोकताक टी और लहाख की पश्मीना स्टोल दी गई। UAE के क्राउन प्रिंस को मिथिला का GI टैग वाला मखाना, जबकि राष्ट्रपति को मेघालय का अनानास और गुजरात का प्रसिद्ध केसर आम भेंट किया गया। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को मध्य प्रदेश की पारंपरिक गॉड पेंटिंग उपहार में दी गई।



एयर इंडिया की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट के इंजन में आग से हड़कंप, यात्री सुरक्षित

दैनिक कारखाने का सफर।
एजेंसी नई दिल्ली

एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एक उड़ान में इंजन में आग लगने की आशंका के चलते गुरुवार शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एक उड़ान में इंजन में आग लगने की आशंका के चलते गुरुवार शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट के इंजन में आग की संभावना बताए जाने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और विमान को आपात स्थिति में उतारा गया।



लैंडिंग करने में सफल रहा। इसके बाद विमान को टो करके ले जाया गया। विमान में कुल 171 यात्री सवार थे। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। घटना के बाद रनवे पर रात 10:18 बजे उड़ान परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम 21 मई 2026 को बेंगलुरु-दिल्ली उड़ान AI-2802 से जुड़ी घटना से अवगत हैं। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और सभी यात्री व चालक दल सुरक्षित हैं। हम अतिरिक्त जानकारी जुटा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे की जानकारी उपलब्ध होते ही अपडेट साझा किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि यह आज एयर इंडिया से जुड़ी दूसरी घटना है। इससे पहले गुरुवार को ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे पर टकरा गया था। दोनों घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। एयर इंडिया ने अभी तक इन घटनाओं पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) दोनों मामलों की जांच कर रहा है।

आज 16 राज्यों में लू, हीट स्ट्रोक और आंधी-बारिश का अलर्ट

दैनिक कारखाने का सफर।
एजेंसी नई दिल्ली

आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभे गिरने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पूर्वी उत्तर

प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर एक सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक एक नया चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। अगले 3-4 दिनों में दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। मौसम विभाग ने 22 मई को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है।

शुभेंदु अधिकारी बोले- बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के बाद बीएसएफ को सौंपें

दैनिक कारखाने का सफर।
एजेंसी कोलकाता

पश्चिम बंगाल में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन घुसपैठियों को पकड़कर कोर्ट मत ले जाओ, बल्कि बीएसएफ को सौंप दो। उन्होंने कहा कि नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालतों में नहीं ले जाएं, बल्कि सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। ऐसा राज्य में एक दिन पहले लागू नियम के तहत किया जाएगा। शुभेंदु ने हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "कल से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा।" बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जिसके तहत राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए घुसपैठियों को निर्वासन के लिए सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। अधिकारी की इस सख्ती से साफ हो गया है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। उन्होंने इसे व्यापक पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो दांचे का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने उस अधिनियम का नाम नहीं बताया जिसके दायरे में बंगाल की नव निर्वाचित भाजपा सरकार ने घुसपैठियों



पर मुकदमा चलाने के लिए यह नीतिगत बदलाव किया है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि शुभेंदु पिछले वर्ष अप्रैल में संघटन द्वारा पारित आत्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 का जिक्र कर रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में आत्रजन, पंजीकरण, निगरानी, हिरासत और निर्वासन के लिए एक आधुनिक, तकनीक-आधारित प्रणाली प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि बांग्लादेश से कोई अवैध प्रवासी, जो संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है, हावड़ा थाने में हिरासत में लिया जाता है, तो उसे अदालत में नहीं भेजा जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को उचित भोजन कराया जाना चाहिए और फिर सीधे बोंगांव के पेट्रापोल सीमा पर या उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट स्थित सीमा चौकी पर बीएसएफ कर्मियों के पास ले जाया जाना चाहिए।" शुभेंदु ने यह भी कहा कि ऐसे बंदियों की संख्या पर साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ)

को प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री को हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने हुगली नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हावड़ा शहर से संबंधित नागरिक अवसंरचना और विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। शुभेंदु ने कहा कि उन्हें इस वर्ष दिसंबर तक हावड़ा और उससे सटे बाली नगर निकायों के वार्ड के परिसीमन का काम पूरा होने की उम्मीद है। इन दोनों शहरी निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित हैं। उन्होंने कहा, "हावड़ा नगर क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की योजना के तहत हमने इस वर्ष के अंत तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने और उसके बाद शहर की जिम्मेदारी निर्वाचित नगर निकाय बोर्ड को सौंपने का फैसला किया है।" अधिकारी ने कहा कि अगले तीन महीनों की अल्पकालिक योजना के तहत प्रशासन स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति, कचरा निकासी बोर्ड को सौंपने का फैसला किया गया।

शैक्षणिक संस्थानों जैसी नागरिक सुविधाओं के उन्नयन पर ध्यान देगा। उन्होंने बताया कि नागरिक अवसंरचना में सुधार के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है, जिसमें रेलवे और नगर निकाय के अधिकारी सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि गतिविधियों की निगरानी नगर मामलों के सचिव खलील अहमद करेंगे। शुभेंदु ने कहा, "हमने हावड़ा में अवैध निर्माणों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और बिल्डरों के एक वर्ग द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू की जाएगी। जिन जलाशयों को पाट दिया गया है, उनके स्थान पर प्रशासन वैकल्पिक जल निकाय विकसित करेगा।" मुख्यमंत्री ने संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग का भी उल्लेख किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु कर रहे हैं। आयोग के सदस्य सचिव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के जयरामन हैं। इस पैनल को 'कट मनी' घोटाले समेत भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है और यह एक जून से आधिकारिक रूप से काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा, "आयोग तेजी से कार्रवाई करेगा। यह साक्ष्य जुटाएगा और जनसुनवाई करेगा, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज होगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी और आगे दंडात्मक कार्रवाई होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि गबन की गई राशि दोषियों से वसूल की जाएगी। शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने हावड़ा शहर पुलिस को राजनीतिक हिंसा, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नयी प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले मुख्यमंत्री को हावड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।

बीएचईएल, भोपाल के सांस्कृतिक भवन में एक दिवसीय पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल



बीएचईएल, भोपाल के सांस्कृतिक भवन में एक दिवसीय पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्व संगठन एवं नेतृत्व से संबंधित व्यापक जानकारी तथा साक्षात्कार से जुड़ी आवश्यक दक्षताओं से अवगत कराना था। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रतिभागियों को बीएचईएल के समग्र स्वरूप, वर्तमान ऑर्डर बुक की स्थिति, विविधोक्ति के प्रयासों, निदेशक मंडल की संरचना, संगठनात्मक ढांचे एवं कंपनी द्वारा आरंभ की गई नई पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

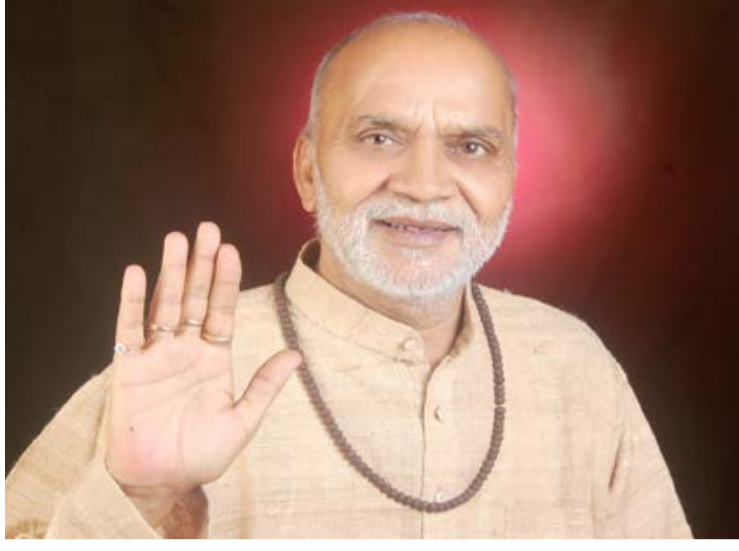
कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को संगठन के व्यापक दृष्टिकोण एवं वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य से परिचित कराना था। द्वितीय सत्र में प्रतिभागियों के व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया, जिसमें व्यवहार कौशल, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण, शारीरिक हाव-भाव, व्यावसायिक आचरण, साक्षात्कार शिष्टाचार तथा प्रभावी संप्रेषण कौशल जैसे महत्वपूर्ण



विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संकाय के रूप में आरिफ अहमद सिद्दीकी, अपर महाप्रबंधक (एचआरडी), मोहित शाह, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (सीपीएक्स), प्रतीक श्रीवास्तव, प्रबंधक (सीपीएक्स) एवं श्री

तरुण कुमार कौशिक, प्रबंधक (एचआरडी) उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उमेश कुमार सावले, प्रबंधक (एचआरडी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुल 147 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

गतांक से आगे : लोक कल्याण हेतु दादाजी का अवतरण



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मैं ज्वाला प्रसाद नामदेव, वर्तमान में अखिल भारतीय नामदेव क्षेत्रिय महासंघ, नई दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। श्री चुन्नीलाल नामदेव दादाजी गुरुदेव साईंखेड़ा वाले के जीवन से जुड़ी यह घटना केवल एक सामान्य प्रसंग नहीं, बल्कि उनकी दिव्य चेतना, मातृभक्ति तथा लोक कल्याणकारी स्वरूप का जीवंत प्रमाण है। यह घटना उस समय की है जब दादाजी लगभग सत्रह वर्ष की आयु में सागर में रहकर सिलाई का कार्य सीख रहे थे। उसी कालखंड में उनकी माता श्री श्रीमती मीराबाई नामदेव अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गईं। उन्हें तेज बुखार था और उनकी स्थिति अत्यंत

चिंताजनक बनी हुई थी। परिवारजन उनकी सेवा में लगे थे, किन्तु दादाजी को इस विषय की कोई सूचना नहीं भेजी गई थी। एक दिन दादाजी सागर में जिस सिलाई की दुकान पर कार्य कर रहे थे, वहाँ वे सामान्य रूप से कपड़े सिलने में व्यस्त थे। उसी समय एक वृद्ध संत स्वरूप बाबा वहाँ से गुजरे। उन्होंने दादाजी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा "तू यहाँ बैठा है और तेरी माताजी साईंखेड़ा में अत्यंत बीमार हैं, उन्हें तेज बुखार है।" यह सुनते ही दादाजी के अंतर्मन में गहरी व्याकुलता उत्पन्न हुई। उन्होंने बिना विलंब किए दुकान के मालिक से कुछ धन उधार लिया और तत्काल बस द्वारा साईंखेड़ा के लिए रवाना हो गए। जब दादाजी अपने घर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। उनकी माताजी तेज बुखार से पीड़ित होकर अत्यधिक

कष्ट में थीं। परिवारजन चिंतित थे और उनकी दशा देखकर वातावरण दुःख से भर गया था। दादाजी शांत भाव से अपनी माताजी के समीप पहुँचे। उनके मुखमंडल पर करुणा, श्रद्धा और आत्मविश्वास का अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनी माताजी के सिर पर हाथ रखा। उपस्थित लोगों ने देखा कि कुछ ही क्षणों में उनकी स्थिति बदलने लगी। धीरे-धीरे बुखार शांत हो गया और उन्हें राहत मिलने लगी। यह दृश्य वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए आश्चर्य एवं श्रद्धा का विषय बन गया। यह घटना केवल एक चमत्कार के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि यह दादाजी के भीतर स्थित दिव्य चेतना मातृसेवा और लोकमंगलकारी शक्ति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में माता को प्रथम गुरु और ईश्वरजल्य

माना गया है। दादाजी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति, सेवा और आत्मिक शक्ति के माध्यम से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। दादाजी का संपूर्ण जीवन लोककल्याण, धर्म, सेवा और मानवता के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनके जीवन में घटित ऐसे अनेक प्रेरणादायी प्रसंग लोगों के हृदय में श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। उनके सान्निध्य में आने वाले लोगों ने सदैव आत्मिक शांति, विश्वास और दिव्य अनुभूति प्राप्त की। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु उन्हें लोककल्याणकारी संत स्वरूप में स्मरण करते हैं और उनके बलाद् मार्ग पर चलकर धर्म, सेवा एवं मानवता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं।

भोपाल की अवैध कॉलोनिनों पर कार्रवाई की चलेगी मुहिम, कलेक्टर ने रेवेन्यू अफसरों की मीटिंग ली, वसूली, सीमांकन-शिकायतें दूर करेंगे



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भोपाल की अवैध कॉलोनिनों पर जिला प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए मुहित चलाई जाएगी। कलेक्टर ने गुरुवार को हुई रेवेन्यू अफसरों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि भूमि आवंटन एवं धारणाधिकार से संबंधित सभी लंबित प्रकरण का आगामी एक माह के भीतर निराकरण तय करें। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में कलेक्टर ने अवैध कॉलोनिनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि वैध एवं अवैध कॉलोनिनों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाए। उन्होंने कॉलोनी सेल को नगर निगम एवं संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आरसीएमएस और लोकसेवा प्रबंधन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक पुराने सीमांकन प्रकरणों का आगामी एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने भू-राजस्व, खनिज राजस्व एवं अन्य शासकीय देयताओं की शत-प्रतिशत

वसूली करने को कहा। उन्होंने भूमि विवादों में कमी लाने के लिए नक्शा शुद्धिकरण, खसरा-खतौनी में त्रुटि सुधार तथा अभिलेखों के अद्यतन कार्य को प्राथमिकता देने पर बल दिया। गुरुवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा बैठक में निर्देश देते। कलेक्टर मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई, कलेक्टर लॉगिन एवं सीएस मॉनिटरिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी एडीएम एवं एसडीएम को रोस्टर बनाकर तहसीलदार न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने और पारित आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह के भीतर सभी लंबित आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। आगामी मानसून को देखते हुए अतिक्रमण, फायर सेफ्टी, पटाखा दुकानों एवं गोदामों के नियमित निरीक्षण, आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की अनुभाग स्तर पर बैठक आयोजित करने को कहा। एडीएम सुमित कुमार पांडे, प्रकाश नायक, अंकुर मेश्राम, पीसी शाक्य सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

संगठित कामगार कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कन्हैया लाल अहिरवार का अभिनंदन

दैनिक कारखाने का सफर। सारंगपुर

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सहमति से संगठित कामगार कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कु रणजीत शक्तावत द्वारा, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह की अनुशंसा पर कन्हैयालाल अहिरवार को कांग्रेस संगठित कामगार कर्मचारी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस संगठित कामगार कर्मचारी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कन्हैया लाल अहिरवार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय ने कहा कि कन्हैया लाल अहिरवार को मिली यह जिम्मेदारी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उनके नेतृत्व से संगठन को नई मजबूती मिलेगी तथा कामगारों और कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।



नवनि्युक्त प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैया लाल अहिरवार ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और

कर्मचारियों व कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वागत कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गा सोमानी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आबिद हुसैन लोदी, वरिष्ठ नेता प्रदीप

सादानी, मोहम्मद अली, राधेश्याम काका, मोहन पाल, समीर मेव, शोएब हसन राही, कैलाश ठाकुर, राधेश्याम वर्मा, रघुवर राजपूत, लखन धनगर, अजय जट्टा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम कारकेड में घुसा आरक्षक लाइन अटैच, भोपाल में VIP इयूटी के दौरान सुरक्षा चूक, 15 घंटे इयूटी करने की बात कहकर दी सफाई

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा इयूटी में तैनात एक आरक्षक की कार सीएम के कारकेड में घुस गई। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे स्टेट हेयर के पास हुई। मामले को गंभीर मानते हुए कोहेफिजा पुलिस ने आरक्षक को हिरासत में लिया और बाद में लाइन लौट कर दिया। पुलिस ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आरक्षक शैलेश अवस्थी वीआईपी इयूटी में तैनात थे। सीएम लखनऊ से भोपाल लौट रहे थे। इसी दौरान स्टेट हेयर से कुछ दूरी पर आरक्षक की कार अचानक सीएम के कारकेड में घुस गई। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार रुकवाई। शुरुआती जांच में शराब पीने जैसी बात सामने नहीं आई है। हालांकि,



वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए विभागीय कार्रवाई की गई। आरक्षक शैलेश अवस्थी जिसे लाइन अटैच किया गया। आरक्षक बोला- अनजाने में कारकेड रूट में पहुंचा आरक्षक ने पुलिस अधिकारियों

को बताया कि वह सुबह 7 बजे से लगातार इयूटी पर थे। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था और देर रात घर जाने की जल्दी में अनजाने में कारकेड के रूट में पहुंच गए। आरक्षक ने बताया कि वह पिछले करीब 10 साल से वीआईपी इयूटी में तैनात हैं। बुधवार रात मुख्यमंत्री के भोपाल पहुंचने के दौरान उनका काम कारकेड रूट पर सुरक्षा व्यवस्था संभालना था। मुख्यमंत्री के दौरे और मुवमेंट के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल पहले से तय रहता है। वीआईपी इयूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां निर्धारित होती हैं। ऐसे में कारकेड के पास किसी भी अनधिकृत वाहन या व्यक्ति की एंट्री को सुरक्षा चूक माना जाता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।



पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा-2026 की मुख्य परीक्षा के पहले बदली रिक्त पदों की स्थिति

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

एमपीपीएससी परीक्षा 2026 के रिक्त पदों की संख्या में लोक सेवा आयोग, इंदौर ने संशोधन किया है। बदलाव के बाद कुल रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। डिप्टी कलेक्टर के लिए 17 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें 15 पद 87 प्रतिशत नियमित श्रेणी और 2 पद 13 प्रतिशत प्रावधिक श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं, उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पदों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। इनमें 16 पद 87 प्रतिशत नियमित और 2 पद 13 प्रतिशत प्रावधिक श्रेणी में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आए आवेदन के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का संशोधित ब्यौरा जारी किया है। आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 04/29/2025 के अनुसार कुल पदों की संख्या अब 156 हो गई है। आयोग ने बताया कि इससे पूर्व में 31 दिसम्बर 2025 को जारी विज्ञापन क्रमांक

29/2025 के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा कराई गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त अपडेट जानकारी के आधार पर रिक्तियों में संशोधन किया गया है। सूची के अनुसार, कुल 140 पद नियमित भर्ती के अंतर्गत और 16 पद बैकलॉग श्रेणी में शामिल किए गए हैं। आयोग के अनुसार, विभागवार पदों का आरक्षण वर्गवार निर्धारित किया गया है। इनमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2026 से संबंधित जानकारी एवं संशोधित रिक्तियों का विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिक्त पदों में प्रशासनिक, वित्त, सहकारिता, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य, राजस्व और अन्य विभागों के पद शामिल हैं। एमपीपीएससी परीक्षा 2026 के रिक्त पदों की संख्या में

लोक सेवा आयोग, इंदौर ने संशोधन किया है। उधर राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को संचालित करने के लिये नए प्रारूप नियमों को तैयार किया है और इन्हें लागू करने से पहले 5 जून 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेशरिया ने बताया कि राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों के प्रारूप विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही सुझाव gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दिए जा सकते हैं। समयवधि के बाद प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भोपाल के अयोध्या बायपास को NGT की अनुमति पर्यावरण से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा, दिल्ली बेंच ने फैसला सुनाया



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

नेशनल ग्रीन ट्रून्सल (NGT) की नई दिल्ली बेंच ने भोपाल के अयोध्या बायपास को अनुमति दे दी है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआई) को पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना होगा। भोपाल के पर्यावरणविद नितिन सक्सेना ने एनजीटी में याचिका लगाई थी। इसी मामले का एनजीटी ने निपटा करते हुए प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय शर्तों के अधीन आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिंह, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सैथिल वेल और सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की। आवेदक सक्सेना ने प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए पर्यावरणीय क्षति, शहरी तापमान में वृद्धि और मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (केंद्रीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान एनएचआई ने एनजीटी को बताया कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। भोपाल में बढ़ते यातायात दबाव, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स और ट्रेफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है। NHAI ने यह भी बताया कि वृक्ष कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गई है और प्रतिपूरक पौधारोपण पर्यावरणीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। दस्तावेजों में अनुमति में कोई अवैधता नहीं एनजीटी ने उपलब्ध दस्तावेजों, रिपोर्ट पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद माना कि वृक्ष कटाई की अनुमति में कोई अवैधता नहीं है। हालांकि, अधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि मध्यप्रदेश वृक्ष संरक्षण कानून एवं पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन हो। ग्रीन हाईवे नीति के अंतर्गत प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य सुनिश्चित करें। वन, नगर निगम, उद्यानिकी विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त तकनीकी समिति 15 वर्ष तक पौधारोपण की निगरानी करें। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को सिफारिशों का पालन किया जाए। साथ ही पिछले ल साल में पौधारोपण एवं CAMPA मद में जमा और उपयोग की गई राशि का विवरण NHAI प्रस्तुत करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि के उपयोग एवं पौधों के जीवित रहने की स्थिति का परीक्षण करते रहे। हरित क्षेत्र जरूरी, पर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना है इस मामले में अधिकरण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं शहरी हरित क्षेत्र का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत



संरचना परियोजनाएं पर्यावरणीय नियमों और प्रतिपूरक उपयोगों के अनुपालन के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही मूल आवेदन एवं लंबित अंतिम आवेदन निराकृत कर दिए गए। बता दें कि एनएचआई भोपाल के अयोध्या बायपास को आसारा चौराहा से रत्नागिरि तिराहे तक 836.91 करोड़ रुपये से 10 लेन में बदल रहा है। यह 16 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 7871 पेड़ काटे जाने हैं, जो 40 से 80 साल तक के हैं। पिछले साल दिसंबर में तीन दिन में करीब आधे पेड़ काट दिए गए थे। इसका जमकर विरोध हुआ। इसके बाद मामला एनजीटी में पहुंचा और 8 जनवरी तक पेड़ों को कटाई पर रोक लगा दी गई थी। इस पर दो-तीन सुनवाई भोपाल बेंच ने की। इसके बाद मामला दिल्ली बेंच में पहुंच गया। इसी मामले में सुनवाई पूरी की गई है। याचिकाकर्ता सक्सेना ने बताया कि पेड़ों की कटाई के मामले में 22 दिसंबर को दिया गया स्थगन फिलहाल बरकरार रहेगा। इस निर्णय से याचिकाकर्ता को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हजारों की संख्या में पेड़ कटाई पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। एनएचआई का अयोध्या बायपास को 10 लेन में बदलने का यह प्रोजेक्ट। पर्यावरणविद ने किया था प्रदर्शन पेड़ों की कटाई का विरोध पर्यावरणविदों ने किया था। पर्यावरणविद सुभाष सी. पांडे, उमाशंकर तिवारी, याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना, सुशय कुलश्रेष्ठ, राशद नूर समेत अन्य लोगों ने कहा था कि पेड़ों को काटकर एनएचआई हरियाली उजाड़ रही है। 10 लेन सड़क



के बदले एनएचआई एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर सकता था, या फिर 10 की बजाय सिक्ससेन बनाने पर जोर दें। जिन पेड़ों को एनएचआई नगर निगम के जरिए काट रहा है, उनकी उम्र 40 से 80 साल तक है। कोंग्रेसी भी कर चुके प्रदर्शन पेड़ों की कटाई को लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेसी रविंद्र साहू झुमरवाला, जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, समेत कई कांग्रेसियों ने मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था। पर्यावरणविद उमाशंकर तिवारी ने बताया कि बायपास के दोनों ओर जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं, उनमें से कई की उम्र 80 से 100 साल या इससे अधिक है। इनके बदले यदि नए पौधे लगाए भी जाएंगे तो उनके पेड़ बनने में सालों बीत जाएंगे। 10 हजार पौधे अयोध्या बायपास के दोनों ओर लगेंगे। इनमें छाया, फलदार एवं शोड-बेयरिंग प्रजाति के पौधे शामिल हैं। इन पौधों की 15 साल एनएचआई देखरेख करेगा। करीब 20 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इस संबंध में केंद्रीय अधिकार समिति को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। नगर निगम के सहयोग से 10 हजार अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जाएगा। नगर निगम ने NHAI को अलग-अलग पार्क, खाली भूमि और सड़क किनारे की उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई है। झिरनिया एवं जागरियापुर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने भूमि दी है, जो राजस्व वन की है। यहां 61 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जून-2026 तक सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी।



पानी और सीवेज लाइनें टूटी... भोपाल में जलसंकट, बाग मुगालिया में लोगों को नहीं मिल रहा पेयजल

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी के कई लोग पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान हैं। पानी और सीवेज की लाइनें टूटने की वजह से सप्लाई प्रभावित हो गई है। कई दिन से यह समस्या है। बता दें कि 17 करोड़ रुपये की लागत से लोक निर्माण विभाग सीमेंटेड सड़क बनाएगा। इसके साथ थिंक गैस द्वारा भी गैस पाइप लाइनें डाली जा रही हैं। खुदाई होने से पानी व सीवेज की लाइनें टूटने से जनता को परेशानी हो रही है। पानी की लाइनें टूटने से रहवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। बावजूद लाइन में समय पर सुधार नहीं किया जा रहा। पानी के लिए परेशान होते लोग। जिम्मेदारों को तुरंत सुधार कराना चाहिए बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि विकास के लिए होने वाले इस कार्य में पानी एवं सीवेज की लाइनें टूट



रही हैं, उनका सुधार संबंधित एजेंसी द्वारा तत्काल करना चाहिए। ताकि जनता को परेशानी ना हो। पानी और सीवेज की लाइनें टूटने की वजह से कई इलाकों में लोग परेशान हैं।

सूबेदार-SI परीक्षा में चयनित युवाओं के 5 जून से इंटरव्यू भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के एसएफएम मैदान में 11 जून तक होंगे फिजिकल टेस्ट

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

सूबेदार और उप निरीक्षक के 500 पदों पर भर्ती के लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB), भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू कराए जाएंगे। इसके लिए 5 से 11 जून 2026 तक भोपाल के लाल परेड मैदान और जबलपुर के 6वीं वाहिनी बिसबल, रांछी स्थित परेड ग्राउंड में प्रक्रिया आयोजित होगी। किस उम्मीदवार का टेस्ट किस केंद्र पर होगा, इसकी जानकारी ESB की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार, ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल तक भोपाल, जबलपुर, सागर और सोधी में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम 18 मई को www.esb.mp.gov.in पर जारी किया गया। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण

के लिए 1166 पुरुष और 473 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल उम्मीदवार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित फिजिकल टेस्ट केंद्र पर पहुंच सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को केवल तय तारीख पर ही उपस्थित होना होगा। फिजिकल टेस्ट की तारीख और केंद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान आधार ई-केवाईसी सत्यापन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार नंबर लॉक न हो। दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी उम्मीदवारों को आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्वयं प्रामाणित फोटोकॉपी भी लेकर उपस्थित होना होगा।



बीएचईएल हॉलिडे होम्स की ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर एआईबीईयू ने सौंपा ज्ञापन

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

बीएचईएल द्वारा संचालित हॉलिडे होम्स की ऑनलाइन आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने की मांग को लेकर ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉइज यूनियन संबद्ध एनएफआईटीयू का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिनांक 21 मई 2026 को एजीएम मानव संसाधन श्रीमती सुरेखा बंधोर से मिला एवं उनके माध्यम से बीएचईएल निदेशक (मानव संसाधन) आदरणीय श्री तजिंदर गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में यूनियन के अध्यक्ष श्री सतेंद्र कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आशीष सोनी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल वाणी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रोहित कुमार उपस्थित रहे। ज्ञापन में यूनियन द्वारा बताया गया कि बीएचईएल हॉलिडे होम्स की आरक्षण प्रक्रिया 22 मई 2026 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है, लेकिन आरक्षण पोर्टल खुलने से पहले ही नैनीताल, शिमला एवं शिलांग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के कमरे 'पूर्व से आरक्षित' दर्शाए जा रहे हैं। यूनियन ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं तथा कर्मचारियों के बीच असंतोष एवं संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है।



यूनियन ने मांग की कि इस मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा भविष्य में सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुदृष्टिहित व्यवस्था लागू की जाए, जिससे किसी भी प्रकार के पक्षपात

की आशंका समाप्त हो सके। एआईबीईयू-एनएफआईटीयू ने कहा कि यूनियन सदैव कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए संघर्षरत रही है और आगे भी कर्मचारियों की आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।

लव जिहाद' के शक में होटल पहुंचे कार्यकर्ता, भानु हिंदू समेत 10 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मारवाड़ी रोड के श्री बालाजी होटल में युवकर तलाशी लेने के आरोप में पुलिस ने कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर केस दर्ज किया है। होटल संचालक राजकुमार वर्मा की शिकायत पर भानु हिन्दू, रावी और अन्य 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। राजकुमार वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 मई की शाम करीब 4 बजे वे होटल पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान भानु हिन्दू, रावी और उनके साथ 10 से 15 लोग होटल पहुंचे। सभी लोगों ने होटल कर्मचारियों से कहा कि होटल में एक हिंदू महिला को मुस्लिम युवक लेकर आया है। इसी शक के आधार पर

वे होटल की तलाशी लेंगे। होटल कर्मचारी ने जब उनसे तलाशी लेने के अधिकार के बारे में पूछा, तब भी समूह होटल के कमरों की जांच करने लगा। इस दौरान होटल का सामान भी अस्त-व्यस्त कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि होटल के खुले कमरों की जांच की गई, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक नहीं मिला। घटना के दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए। होटल संचालक राजकुमार वर्मा का कहना है कि इस घटनाक्रम से होटल की छवि और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुलिस को होटल के CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



एमपी में मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनेगा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा भी जल्द शुरू होगी, 1164 मार्गों पर दो साल में चलेंगी 5206 बसें

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस योजना में 1164 मार्गों पर दो साल में 5206 बसें शुरू करने की तैयारी है। उधर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन किया जा रहा है। जिससे ज़रूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें। दूसरी ओर जनजातीय कार्य विभाग और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठकों में सीएम के तेवर तल्ख रहे और प्रमुख सचिवों को नाराजगी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को हुई परिवहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। अधिकारियों को शीघ्र ही इंटीग्रेटेड करने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राह-वौर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में मानव संसाधन की कमी की पूर्ति

अभियान चलाकर की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मीपिंग करा ली जाए, जिससे ज़रूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें। विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, जिससे दुर्घटना क्षेत्रों में ज़रूरतमंद तक 30 मिनट से भी कम समय में एम्बुलेंस ऑटो मोड (जो सॉफ्ट से निकटतम हो) में पहुंच जाए। बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित पीएम-राहत योजना एवं राहवौर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पीएम-राहत योजना में राज्य के सभी 55 जिलों में जिला नोडल अधिकारियों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है। योजना में कुल 2,298 प्रकरणों में से 1692 प्रकरण अनुमोदित कर दिए गए हैं। राह-वौर योजना में कुल 109 आवेदन मिले, इनमें से 49 प्रकरण मंजूर कर लिए गए हैं। बालाघाट जिले में राह-वौर योजना पर बहुत अच्छा काम हुआ है। बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग से 'म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय' का गठन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग को दिए गए 4,400 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 4911.78 करोड़ रुपये राजस्व आय

अर्जित की गई। लक्ष्य से विभाग द्वारा 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 5,721 करोड़ रुपये राजस्व आय का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना दो चरणों में चलाई जाएगी। प्रदेश में 7 क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, भोपाल (मंसदापुर सहित), जबलपुर, सागर, ग्वालियर (चंबल सहित) एवं रीवा (शहडोल सहित) स्थापित किए गए हैं। पहले चरण में चलाई जाने वाली बसों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों से उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित मार्ग मंजूरी की विभागीय अभिसूचना भी जारी कर दी गई है। अन्य क्षेत्रों के विस्तारित मार्गों की अभिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के कुल 1,164 मार्गों पर लगभग 5,206 बसों का संचालन अगले दो सालों में किया जाएगा। इन सभी बसों की सुचारु भौतिकीय के लिए एक दक्ष एवं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में इंदौर क्षेत्र के कुल 121 मार्गों में कुल 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र के 120 मार्गों में 371 बसें, भोपाल क्षेत्र के 104 मार्गों में 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र के 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र के 92 मार्गों में 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र के 65 मार्गों में 298 बसें तथा रीवा क्षेत्र के 35 मार्गों में 184 बसें चलाई जाएंगी।

मणिपुर में अराजक हाल!



अफसोसनाक है कि मणिपुर में हिंसा का दायरा फैलने के बावजूद राष्ट्रीय चर्चा में ये राज्य अब हाशिये पर है। ऐसी बेपरवाही आगे चल कर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। मणिपुर के कई हिस्सों में सरकारी तंत्र का निर्वन्नाग ना के बराबर रह गया है। अलग- अलग समुदाय से संबंधित हथियारबंद गुट अपने प्रभाव वाले इलाकों में हत्या, अपहरण, इलाका-बंदी और आम जन-जीवन को ठप करने जैसी गतिविधियां बेकाबू ढंग से चला रहे हैं। फिलहाल, कुकी-जो और नगा समुदायों के बीच ठनी हुई है। 13 मई को तीन पादरियों की हत्या के बाद से कांगपोकपी और सेनापति जिलों में हालात तनावपूर्ण हैं। उसी रोज कुकी-जो और नगा गुटों ने एक-दूसरे समुदाय के लगभग 40 लोगों का अपहरण कर लिया। उन गुटों ने आपसी सहमति के तहत 15 मई को 12 नगा और 14 कुकी बंधकों को रिहा कर दिया। मगर कुकी गुटों का दावा है कि उनके 14 लोग अभी भी नगा गुटों के पास हैं। इस बीच नगा समूहों ने अपने इलाके में राजमार्ग की बंदी कर रखी है, जिससे पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र का परिवहन प्रभावित हुआ है। सेना और अर्धसैनिक बलों ने बंधकों को छुड़ाने की मुहिम चलाने का एलान किया है, लेकिन मोटे तौर पर उनकी भूमिका निष्प्रभावी रही है। पिछले फरवरी में मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनी, लेकिन उसके कार्यकाल में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मैतेई, कुकी-जो और नगा गुटों के बीच हिंसा और अशांति का माहौल लगातार बना हुआ है। अब कुकी-जो संगठनों ने खेमचंद सरकार को बर्खास्त कर राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मैतेई संगठन भी मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं। इस बीच नगा और कुकी-जो के बीच टकराव बढ़ गया है। मणिपुर को हिंसा की चपेट में गए तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं। अफसोसनाक है कि राज्य में सामुदायिक खाईएं चौड़ी होने तथा हिंसा का दायरा फैलने के बावजूद राष्ट्रीय चर्चा में ये राज्य अब हाशिये पर है। ऐसा लगता है कि वहां से आने वाली खबरें विषय या मीडिया के लिए भी अहम नहीं रह गई हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि उत्तर-पूर्व के इस महत्वपूर्ण राज्य को लेकर ऐसी बेखबरी आगे चल कर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकती है।

कांग्रेस रूपी में सौ से ज्यादा सीट मांगेगी



पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही पार्टियों ने अगले साल के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें भाजपा सबसे अगुवा है और हर राज्य की प्रादेशिक पार्टियां भी उसके मुकामबले के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने भी समय से पहले शुरूआत की है। कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खास कर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, जहां अगले साल मार्च में विधानसभा का चुनाव होना है। जनवरी के अंत तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसका अर्थ है कि अब सात महीने का समय बचा है। पहले दौर में पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव है। इनमें से उत्तर प्रदेश छोड़ कर कांग्रेस बाकी चार राज्यों में चुनाव जीत कर सरकार बनाने की संभावना देख रही है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसका फोकस उत्तर प्रदेश पर है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिल कर लड़ा था। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, जिनमें से कांग्रेस छह पर जीती। यानी औसत 33 फीसदी जीत का रहा। दूसरी ओर सपा 63 सीटों पर लड़ कर 37 पर जीती। यानी उसका औसत 60 फीसदी जीत का रहा है। तभी सपा के नेता चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहे लेकिन सपा ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने अभी से एक सीट से ज्यादा सीट की दावेदारी शुरू कर दी है। केरलम में सरकार गठन के तुरंत बाद राहुल गांधी दो दिन के रायबरेली दौर पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बाड़ा ने नेताओं के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने प्रदेश कमेट्री से हर सीट पर पांच संभावित उम्मीदवारों के नाम देने को कहा है। पहले चरण में कांग्रेस 22 सीट से ज्यादा नाम मंगा रही है। उसके बाद वह एक सीट से 102 सीट पर फोकस करेगी। हर सीट पर पहले पांच और फिर तीन सीरियस उम्मीदवारों की सूची बनेगी। दूसरी ओर सपा का कहना है कि सीटों का संख्या पर तो आगे बात हो जाएगी लेकिन कांग्रेस अगर गठबंधन के लिए अनुकूल सीटों पर ही दावेदारी कर देगी तो मुश्किल होगी। यानी नंबरस से ज्यादा क्वालिटी सीट पर विवाद होगा।

लोकतंत्र में कॉकरोच, चीन में रोबोट!

समय का ही फेर है जो सब कुछ बेतुका है! जैसे ट्रंप क्यों चीन गए? क्या पाया? नरेंद्र मोदी नौदरलैंड गए तो वहां से भारत को क्या प्रवासी भारतीयों का नाच-गाना मात्र देखा था? ताकि भक्तों को लगे नौदरलैंड में भी अपनी संस्कृति के सुनहरे दिन हैं। ऐसे ही यूएई में शेख के साथ तेल-गैस सप्लाय के करार की वीडियो झांकियां ऐसी थीं कि बस आया वहां से इंधन और गैस। सो, लोकतंत्र अमेरिका का हो या भारत का या ब्रिटेन, सभी तरफ लोकभावनाओं से ऐसा खेला जा रहा है जैसे मनुष्य प्रजाति अब सिर्फ उल्लू बनने के लिए है! पर उल्लू मात्र क्यों? लोकतंत्र सर्वत्र "एनिमल फार्म" में कनवर्ट है। भेड़, बकरी, सुअर, लोमड़ी, भेड़िए, केकड़े, बिच्छू, मच्छर, सांप-सपैरों की पहचान लोकतांत्रिक देशों में अलग-अलग तरह से प्रकट होती हुई है। पिछले सप्ताह भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मनुष्य की एक नई किस्म का ज्ञान दिया। बताया कि भारत में 'कॉकरोच' की तरह बहुत से युवा हैं, जिन्हें इस पेशे (वकालत) में रोजगार नहीं मिल रहा है। वे सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म में लगे, काले चोगे पहनकर घूम रहे हैं! सोचें, दुनिया दो-तीन सौ साल पहले हिंदुस्तान को सांप-सपैरों, ठगों का देश कहती थी। आज अमेरिका से परिभाषित 'नरककुंड' भारत में अजैविक भावना भी है तो मनुष्य कॉकरोच-सा जीवन जीते हुए भी। उनके बीच प्रतिस्पर्धा केकड़े हैं। भेड़-बकरियां हैं। 'परजीवी' कीड़े-मकोड़े हैं। सत्ता के भूखे सुअर हैं, लालच-लूट के लिए जीभ लपलपाते भेड़िए हैं। सोचें, ऐसा होना कैसे हुआ? दोष अंग्रेजों का, गांधी-नेहरू का कतई नहीं है। अंग्रेज हिंदुस्तानियों को स्वाधीन बना गए थे। साफ-सुथरे चुंगुणों के साथ लोकतंत्र, नए जमाने की हवा-पानी दे गए थे। जिनहोंने पढ़ा-लिखा है वे जानते कि 1947 से पहले वकालत, जज, मुक्किल का मान-सम्मान और हैसियत क्या थी और अब क्या है? तब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे शासकों की बीन पर नाचते चीफ जस्टिस नहीं होते थे। न ही जज भय से, पदोन्नति के लिए, राज्यसभा की सांसदी के लिए, रिटायर होने के बाद पद की भूख में नेताओं के घरों में कॉकरोच की तरह प्रकट होते थे। तब न आज जैसी शिक्षा, राजनीति, अफसरी, अदालत, चिकित्सा, खानपान की मिलावटी व्यवस्था थी। अब वह आबोहवा है, जिसमें कॉकरोचो सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ हैं वही बेचारे लोग शासन की फाइलों, न्याय की आंकाशाओं, कृपा के इंतजार में सालों से फंसे कीड़े-मकोड़े! समझ न आने वाली बात है कि बेचारे काले चोगे वाले ही क्यों कॉकरोच। चीफ जस्टिस यह क्यों भान नहीं हुआ कि फाइलों में न्याय का इंतजार कर रहे करोड़ों-करोड़ लोग क्या हैं? उन्हें भी क्यों नहीं वैसे ही निपटा दिया जाता जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परिचय बंगाल के 27 लाख 4,283 कॉकरोचों (दस्तावेज लिए कथित नागरिकों-मतदाताओं) को यह कहकर निपटारा कि इनका वोट डालना कोई जरूरी नहीं है! बहरहाल, ऐसा संकट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस यानी लोकतंत्र के प्रतिमान देशों में नहीं है। बावजूद इसके इन्हीं से दुनिया में लोकतंत्र की साख घटती हुई है। गुजरें सप्ताह चीन में ट्रंप और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की दशा-दिशा पर वैश्विक मीडिया में हुई टीका-टिप्पणी से जाहिर था कि ब्रिटेन शासन समर्थ (governable) नहीं रहा तो चीन से ट्रंप मायूस, हाताश लौटा। शी जिनपिंग ने अपना जलवा दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं दो मानव चेतना, मानवाधिकारों, मनुष्य स्वतंत्रता की ललक रखने वाले सुधीजन भी चीन, रूस, उत्तर कोरिया यानी तानाशाही के तंत्र को प्रभावशाली व सही समझने लगे हैं। मतलब चीन को देखो, उसके नेता शी जिनपिंग को देखो। वहां स्थिरता है। विकास है! व्यवस्था, नेतृत्व, रिश्तों आदि हर कसौटी में चीन बेहतर है जबकि लोकतांत्रिक देशों में कहीं शासन मुश्किल हो गया है, कहीं जंगलराज है और कोई देश एनिमल फार्म जैसा! हां, चीन लोगों के दिमाग में पेट रहा है। उसकी तस्वीर से लोकतंत्र साख गंवा रहा है। इसका आगे अर्थ



होगा पृथ्वी के आठ अरब लोगों की भेड़चाल में होमो सेपियन की नियति का बंधना। चीन, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया जैसी नियति। निरंकुशता तथा धार्मिक-सभ्यतागत अहंकारों में मनुष्यों का बंधना। कल्पना करें, चीन वैश्विक धुरी बना। तो वर्चस्व, एकछत्रता की इस धुरी से भारत सहित दक्षिण एशिया, आसियान देश, अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोशिया, लातिनी अमेरिकी देशों तक में वही रक्षक, पालक, मददगार, विकास मॉडल में आदर्श बना हुआ होगा। तब बीस-तीस साल बाद दुनिया कैसी होगी? यह बड़ा विषय है। जवाब एक कॉलम में देना संभव नहीं है। लेकिन ट्रंप की चीन यात्रा और ब्रिटेन में सरकार की स्थिरता के संकट की हकीकत में इतना भर जानना चाहिए कि चीन मनुष्य को मशीन में परिवर्तित करने का वह पुराना बाड़ा है, जिसकी सफलता मनुष्य प्रजाति के मशीन बन जाने से है। पत्रकारिता के भरे पचास वर्षों का अनुभव है कि कम्युनिस्ट सरकारों, निरंकुश-फासीवादी सरकारों (स्पेन के फ्रांको से लेकर पोल पॉट के कंप्यूचिया, ब्रेजेनेव के सोवियत संघ से माओ के चीन के अनुभवों के तमाम रंगों को बाकयादा समझते हुए) का अर्थ केवल एक है और वह नेता-अहंकार विशेष की सनक से मनुष्य का मशीन में कनवर्जन। सोचें, चीन नाम की अस्सी साला आधुनिक मशीन पर! माओ के समय आबादी बेइंतहा बढ़ रही थी, तो माओ और कम्युनिस्ट पार्टी ने मनुष्यों से कहा- बच्चे कम पैदा करो। सत्ता ने बटन दबाया और बच्चे कम पैदा होने लगे। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग की सनक है कि बच्चे ज्यादा पैदा हों। बटन दबा और खबर मिलने लगी है कि जनसंख्या दर में उठाव है! माओ, देंग से शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट अनुशासन की सभ्यतागत विरासत में चीन के लोगों को हर तरह की कोशिश से उन्हें उत्पादकता की मशीन बनाया। जीने का मशीनी मिजाज बना। तभी सोचें, चीन में ही शोध करते हुए, वही रहते हुए तू यूयू नाम की महिला अकेली वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, जिसे मलेशिया के खिलाफ नई चिकित्सा पद्धति की खोज के लिए 2015 में नोबेल पुरस्कार कर्मियों ने सम्मान लायक माना। जबकि प्रगति के कथित विकास अनुसार तो नोबेल पुरस्कारों में भी उसे अमेरिका, यूरोप को पछाड़ देना था। चीन इसलिए बना क्योंकि 1971-72 में राष्ट्रपति निक्सन, हेनरी किंसिंजर, रिपब्लिकन पार्टी और पूंजीपतियों ने अमेरिका में ब्यूयू कॉलर मजदूर संगठनों के आंदोलनों से तंग आ गए थे। तब चीन में फैक्ट्रियां लगाने का आइडिया पसना। 1972 में माओ ने लाल क्रांतिनि विद्यवाकर राष्ट्रपति

निक्सन को आठ दिन चीन घुमाया। और अमेरिकी पूंजीपतियों का कारखाने लगाना शुरू हुआ। कम्युनिस्ट मशीनरी ने चीनियों को दिन-रात फैक्ट्रियों में झोंके रखा। चीन दुनिया की फैक्ट्री बना। यही चीन नाम के 'मशीनी देश' की सफलता का बीज मंत्र है। कुल मिलाकर मनुष्य से उसकी "स्वतंत्र चेतना" को छीन कर उससे वैसे ही काम कराना जैसे इलाय मशीन से काम करता है। और त्रासद

है जो अब वह मशीनी लोगों से रोबोट बनवाकर उन्हें दुनिया के आगे नाचता, दौड़ता दिखला रहा है। इसका असर है कि लोकतांत्रिक देशों के अलग-अलग मिजाज के मनुष्य चीन पर सोचते हैं कि चीन सब कुछ बना रहा है, बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है। शंघाई, बीजिंग से लहासा सहित शहरी इलाका हो या देहाती, चौतरफा विकास ही विकास है। मतलब "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के बिना भी जीना मनुष्य का असल जीवन है। पर चीन का जो 'असल', कथित 'विकास' रोबोट है वह उस वैश्विक दिमाग, बुद्धि, बौद्धिक उर्वरता, स्वतंत्रता से अनंत उड़ान लिए उन हंसों की बदौलत है जो आज बुद्धि, दिमाग को ही कृत्रिम बना दे रहे हैं। यों उनकी नकल, जुगाड़ में चीन ने भी अपने एआई मॉडल बनाए हैं। मगर वह सब अमेरिका की सिलिकॉन वैली, तकनीक, आईटी के ज्ञान-विज्ञान-शोध-वैचार से है। जिनकी छाया में चीनी कंपनियां, सरकार भी अपने स्तर पर जुगाड़ बनाती हैं। ट्रंप के आगे शी जिनपिंग का यह दबाव है कि उनके प्रशासन में चीनी नौजवानों के अमेरिकी विश्वविद्यालय के दाखिलों, वीजा, उनके पढ़ने-सीखने की गरिमा का बाजा बजाया है (कल्पना कर सकते हैं कि ट्रंप से मुलाकात में ऐसे नरेंद्र मोदी भारत के छात्रों का मुद्दा उठाएं)। मतलब यह कि अमेरिका ने सत्तर-अस्सी के दशक में चीन को अपनी फैक्ट्री, चीनियों को अपनी मशीन बनाया तो वैसे अमेरिकी मेधा अब एआई से मनुष्य को ही 'प्रोग्राम्ड नागरिक' के वैश्विक प्रेम में ढाल दे रही है। देशों के लोगों को को धीरे-धीरे एल्गोरिथ्म से रोबो या "डेटा-पशु" बना रही हैं। अमेरिकी-यूरोपीय एआई कंपनियों वह समूल ले आ रही हैं, जिससे लोकशाही हो या तानाशाही, सभी उस अनाम "डिजिटल-प्रोग्राम्ड नागरिक यानी मशीनी सिस्टम" से संचालित होंगे, जिसमें गलत कुछ नहीं होगा। हर तरह के कॉकरोच और रोबोट दोनों उसके अधीन क्योंकि इस नकली बुद्धि में भरी हुई सत्य की कसौटी में है। सवाल है क्या तब तक लोकतंत्र ढह नहीं चुके होंगे? मैं नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को चाहे जितना बिगाड़ दें या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ में ट्रंप जैसे बेवकूफ बनाने वाले कितने ही दक्षिणपंथी नेता शासन में आ जाएं, इन देशों में मनुष्य गरिमा के साथ वह मखौल कभी नहीं बनेगा जैसा चीन ने लोगों को मशीन बनाकर बनाया है या भारत में जैसे कॉकरोच, फर्जी, संदिग्ध, परजीवी, भक्त, भयाकुल बनाकर मनुष्यता की मानव गरिमा के गटर बना दिए हैं।

-हरिशंकर व्यास

नेता दिखावा बंद करें तो कुछ काम हो!

वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है लेकिन राजनीति की बात करें तो भारत एक प्रदर्शन प्रधान देश है। यहां नेता कई तरह की कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में जैसी महारत भारत के नेताओं को है वैसी दुनिया के किसी देश के नेता में नहीं होगी। तभी देश और दुनिया में तेल का संकट शुरू हुआ तो दुनिया भर के देशों ने अपने यहां इस संकट से निपटने के उपाय किए। भारत में पहले तो 70 दिन तक संकट को स्वीकार ही नहीं किया गया क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव होने थे। चुनावों में बेहिसाब रैलियां हुईं, रोड शो हुए, नेताओं के विशेष विमान उड़ते रहे। राध्प ग्रहण समारोह तक यह तमाशा चला। उसके बाद अचानक तेल के संकट की याद आई और दूसरे तरह का दिखावा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल, डीजल, गैस आदि किफायत से खर्च करने को कहा। मिसाल बनाने के लिए एक दिव्य वे भी दो गाड़ियों के काफिले से निकले। उसके बाद नेताओं ने जो तमाशा शुरू किया है वह लोगों के लिए सिरदंद बन गया है और सोशल मीडिया को



कई महीनों तक के लिए मीम्स और मजाक का मसाला मिल गया है। भाजपा के नेताओं में होड़ मची है कि कौन कितने क्रिप्टिव तरीके से दिखावा कर सकता है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक दिन मेट्रो पकड़ी। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समझ में आया कि यह तो अच्छा तरीका है मीडिया को दिखाने के लिए तो वे भी एक दिन मेट्रो से चलीं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में खबर आई कि उन्होंने अपने काफिले

में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने सबको पीछे छोड़ते हुए एक दिन बाइक चलाते हुए सचिवालय जाने का फैसला किया। सो, वे और उनके साथी डेर सारे लोग बाइक चलाते हुए ऑफिस गए। राजस्थान में एक जज सक्लाने ने साइकिल से अदालत जाने का फैसला किया तो बिहार के मुख्यमंत्री समाट चौधरी ने सबको पीछे छोड़ते हुए पैदल ही ऑफिस जाने का फैसला किया। वे पैदल चल कर सचिवालय गए। अब देखना है कि इससे आगे की क्रिएटिविटी कौन दिखाता है! लेकिन अब सवाल है कि कोई बाइक से या साइकिल से या पैदल ऑफिस गया तो पूरे समय की वीडियो बनाने का काम किसने कर सकता है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक दिन मेट्रो पकड़ी। फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समझ में आया कि यह तो अच्छा तरीका है मीडिया को दिखाने के लिए तो वे भी एक दिन मेट्रो से चलीं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में खबर आई कि उन्होंने अपने काफिले

किसी नेता का कोई वीडियो सामने नहीं आया है, जिसमें वह शाम में थका हारा कार्यालय से लौटता हुआ दिखे। तभी ऐसा माना जा रहा है कि नेता बाइक या साइकिल से या पैदल सचिवालय पहुंचा। फिर पीछे से उसकी गाड़ियां गईं, जिनसे वह शाम में या दिन में किसी समय वापस लौटा। अब सोचें, जब गाड़ियां पीछे से जानी ही हैं तो फिर सुबह जाते समय दिखावा करने की क्या जरूरत है? लेकिन दिखावा इसलिए करना है कि भाजपा के सर्वोच्च नेता खुद भी दिखावा करते हैं और दिखावा पसंद भी करते हैं। यह भी तो सोचें कि जो काम वे खुद कर रहे हैं वही काम करने से किसी को कैसे रोक सकते हैं? सो, इस समय देश में दिखावा काल चल रहा है। बाकी पेट्रोल, डीजल और गैस का जो संकट है वह अपनी जगह है और इनके दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ रही है वह भी अपनी जगह है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सोना खरीदना बंद करने और विदेश यात्रा रोकने की अपील की थी। अब देखना है कि भाजपा के लोग कब सुनार की दुकानों और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के बाहर लाठी लेकर खड़े होते हैं, लोगों को रोकने के लिए!

जनता का शुक्रिया कहिए, अहसान मत जताइए!

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ कॉमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी। उसके बाद पेट्रोल, डीजल और सीपनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कह सकते हैं कि जितनी आशंका जताई जा रही थी उसके मुकामबले कम बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह तो शुरूआत है। अभी इस बढ़ोतरी का असर दिखना बाकी है। उससे पहले ही दूसरे कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। असल में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ोतरी का बड़ा असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होंगी या उत्पादन घटाएंगी। इससे प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट होगा। मध्य वर्ग के लिए भी कई तरह की समस्याएं होंगी। यह समूह तो रुपय की गिरती कीमत और शेयर बाजार में हुए नुकसान से भी बहुत प्रभावित हुआ है। जिस उम्मीद में लोग सिप और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे, वह सारी उम्मीदें टूट गई हैं। सो, अलग अलग किस्म की समस्याएं हर वर्ग के सामने आने वाली हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के बारे में सवाल उठे तो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की जनता पर अहसान जताते हुए कहा कि सरकार जनता पर कम से कम बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की जंग से जो समस्या आई है उसका शॉक सरकार अपने ऊपर झेल रही है। यानी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद तेल उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होने से जो कीमतें बढ़ी हैं उनका शॉक सरकार बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने कहा नहीं लेकिन उनके कहने का आशय यह था कि चुनाव तक शॉक सरकार बर्दाश्त कर रही थी, अब जनता बर्दाश्त करे। प्रधानमंत्री को बातें भी इसी दिशा में इशारा कर रही हैं। उन्होंने तो नौदरलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों के सामने कहा कि अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो 10 साल में जो कुछ हासिल हुआ वह सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यह पॉजिशनिंग है वह बताते के लिए कोराना, युद्ध और तेल के संकट के कारण उपलब्धियां कोई खास नहीं दिख रही हैं। बहरहाल, सवाल है कि पेट्रोलियम मंत्री, उनके मंत्रालय के अधिकारी या दूसरे नेता जनता के ऊपर जो अहसान जता रहे हैं, वैसे करने को इजाजत किसी सभ्य लोकतंत्र में हो सकती है?



क्या कोई भी चुनी हुई सरकार, जो नागरिकों के टैक्स से पैसे से चलती है वह नागरिकों पर अहसान जता सकती है? क्या इतनी बेसिक बात मंत्री को समझ में नहीं आती है कि शॉक सरकार नहीं बर्दाश्त कर रही है? वह शॉक भी जनता ही बर्दाश्त कर रही है। जनता ही टैक्स चुका रही है, जिसके पैसे को इधर से उधर घुमा कर सरकार कहती है कि वह जनता पर अहसान कर रही है। एक मई को सरकार ने इस बात का उल्लेख मनाया कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड दो लाख 43 हजार करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिले हैं तो ध्यान रखें कि वह पैसा जनता ने ही दिया है। दूसरी बात यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हुई थी तो क्या सरकार ने देश की जनता को उसका लाभ दिया था? अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो कीमत अब बढ़ी है लेकिन हकीकत यह है कि 2014 के बाद से ही अलग अलग कारणों से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत कम रही है। एक समय तो एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 40 डॉलर से भी नीचे पहुंच गई थी। फिर भी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। सरकार ने पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को लूट की खुली छूट दे रखी

सरकार को यह नहीं बताना चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से हुई 45 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च हुए? ध्यान रहे यह टैक्स जीएसटी और आयकर से अलग है। उन दोनों मद में सरकार 35 से 40 लाख करोड़ रुपए की सालाना वसूली अलग कर रही है। फिर भी सरकार चल रही है कर्ज के सहारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत के मामले में सरकार अहसान जता रही है। दूसरे सेक्टर में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर रेलवे की टिकटों में होता है। टिकट भी सरकारों कहती थीं कि वह सब्सिडी देती है लेकिन यह सरकार तो पहले पर लिखने लगी है कि इसमें 43 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि वह 43 फीसदी सब्सिडी सरकार में बैठे लोग अपनी जेब से नहीं देते हैं। देश के नागरिकों का ही पैसा होता है। लेकिन गरीब और मध्य वर्ग जो ट्रेन में सफर करता है उस पर अहसान किया जाता है। विडंबना देखिए कि यह सब्सिडी चिड़िया के चुगुगे के बराबर है। लेकिन दूसरी ओर बड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों को जो भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है वह ऐसा लगता है जैसे उनके अधिकार

के तौर पर दी जा रही हो। हकीकत यह है कि एक रुपए एकड़ की दर पर जो जमीन किसी उद्योगपति को दी जा रही है या किसी कारोबारी का हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बड़े खाते में डाला जा रहा है या 57 हजार करोड़ रुपए का कर्ज 11 हजार करोड़ में सेटल किया जा रहा है वह अहसान करना होता है। जनता के पैसे से सरकार कारोबारियों, उद्योगपतियों पर अहसान करती है। लेकिन उसे उलटे यह प्रचारित किया जाता है कि 57 हजार करोड़ रुपए का कर्ज 11 हजार करोड़ में सेटल करके कारोबारी देश पर 'अहसान' कर रहा है। इसका अर्थ है कि सिर्फ वोट मांगने के समय ही 'मतदाता मालिक' बाकी समय वह भिखमंगा है, जिस पर अलग अलग तरह से अहसान किया जाता है। बाकी समय देश के बड़े उद्योगपति, कारोबारी और खुद नेता मालिक होते हैं। सरकार कह रही है कि एक लीटर पेट्रोल पर 14 से 18 रुपए, एक लीटर डीजल पर 18 से एक सी रुपए तक और 14 किलो के रसोई गैस सिलेंडर पर करीब चार सौ रुपए की अंडर रिक्वरी हो रही है यानी इतना नुकसान उठा कर जनता को ये उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सवाल है कि इसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? क्या सरकार के पास कोई गुप्त खजाना है, जिसमें नेताओं के प्रताप से पैसे आ रहे हैं और उससे घाटे की भरपाई हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ उसी जनता के टैक्स से हो रहा है, जिस पर अहसान लादा जा रहा है। नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के बड़े बड़े बंगले, भारी भरकम वेतन, भत्ते और मौज मस्ती का सारा सामान जनता जुटा रही है। अगर इसमें कहीं कमी रह जा रही है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है तो वह कर्ज भी जनता को अपने खुना पसीने की कमाई से चुकाना है। किसान की हाड़ तोड़ मेहनत से उपजाया हुआ अनाज मुफ्त में बांट कर वोट लिया जा रहा है लेकिन किसान पर अहसान यह है कि तुम्हारे उत्पाद का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया या तुम्हको खाद और बीज पर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। सोचें, टैक्स के पैसे से ही सब्सिडी दी जाती है, लेकिन टैक्स के लिए शुक्रिया कहने की बजाय सब्सिडी का अहसान जताया जाता है! जनता का शुक्रिया कहिए कि ऐसे कठिन समय में भी वह आपका खजाना भर रही है, उस पर अहसान मत जताइए!

-अजीत द्विवेदी

चीन की 'रोबोट सेना' ने बनाया चोंगकिंग स्टेशन, एलन मस्क दंग

एजेंसी वॉशिंगटन

पिछले हफ़्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाई-प्रोफाइल अरबपतियों के दल के हिस्से के तौर पर चीन की यात्रा के दौरान, टेक दिग्गज एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो रीपोस्ट किया। यह वीडियो 'चोंगकिंग इंस्ट रेलवे स्टेशन' के निर्माण की हैलअपोज यात्रा का था। सार्वजनिक परिवहन को लेकर हमेशा शंका जाहिर करने वाले मस्क का यह पोस्ट दुनिया भर में कौतूहल का विषय बन गया। कौतूहल से इतर, चोंगकिंग इंस्ट रेलवे स्टेशन की असली कहानी बेहद दिलचस्प है। यह कहानी बताती है कि कैसे चीन ने रोबोट की एक पूरी सेना का इस्तेमाल करके सिर्फ 38 महीनों में दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का निर्माण कर दिया। फ्लोर परिया के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी-मॉडल ट्रांजिट कॉम्प्लेक्स है, जिसे मई 2025 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। दक्षिण-पश्चिमी चीन के अंदरूनी हिस्से में स्थित चोंगकिंग, जहाँ यह स्टेशन बना है, आबादी और प्रशासनिक क्षेत्र, दोनों ही मामलों में देश का सबसे बड़ा शहर है। आज एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन चुका चोंगकिंग, 1960 के दशक में माओ जेडोंग के 'थर्ड फ्रंट कैम्पेन' के तहत पूरी तरह से बदल गया था। यह एक बहुत बड़ा प्रयास था, जिसके तहत देश के विशाल संसाधनों को चीन के उन अंदरूनी इलाकों के तेजी से औद्योगीकरण की ओर मोड़ दिया गया, जिनकी पहले ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उद्योग प्रशांत तट से पश्चिम की ओर फैल गए। आज, चोंगकिंग और उसका नया स्टेशन, चीन की जबरदस्त इंजीनियरिंग क्षमता और उसकी विशाल आर्थिक ताकत का एक शानदार नमूना है। यह वही चीनी शहर है, जहाँ आपको अपार्टमेंट की इमारतों के बीच से गुजरती हुई मेट्रो ट्रेनें दिखाई देंगी। जहाँ कई देश बड़े पैमाने की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दशकों तक संघर्ष करते रहते हैं, वहीं चीन ने इस विशाल 1.22 मिलियन वर्ग मीटर के स्टेशन को सिर्फ 38 महीनों में ही बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ बताया गया है कि कैसे रोबोट की एक सेना ने मिलकर इस स्टेशन का निर्माण किया। स्टेशन के बारे में विस्तार से जानने से पहले, उस शहर के बारे में समझना जरूरी है, जिसके पीछे यह स्टेशन बना है। चोंगकिंग चीन के सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील विशाल शहरों (megacities) में से एक है। शंघाई और बीजिंग जैसे चीन के कई अन्य शहरों के केंद्रों की तरह ही, चोंगकिंग भी एक प्राचीन शहर है, जिसका इतिहास लगभग 3,000 साल पुराना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, 1937 में जापानी सेनाओं के हाथों पिछली राजधानी, नानकिंग के पतन के बाद, इसने चीनी राष्ट्रवादी (KMT) सरकार की राजधानी के रूप में कार्य किया। 1960 के दशक में ही चोंगकिंग वास्तव में चीन के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक के रूप में उभरा। यह शहर 'थर्ड फ्रंट अभियान' का एक प्रमुख लाभार्थी बना; यह माओ जेडोंग द्वारा निर्देशित एक विशाल औद्योगीकरण अभियान था। रणनीतिक गहराई बनाने के उद्देश्य से, इस अभियान ने विशाल औद्योगिक



निवेश को चीन के समृद्ध तटीय क्षेत्रों से हटकर, ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित आंतरिक क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया, ताकि औद्योगिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को संभावित सोवियत आक्रमण या अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया जा सके। इसने रक्षा, भारी उद्योग, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। इस अभियान से मुख्य रूप से चीन के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में स्थित आंतरिक प्रांतों को लाभ हुआ। जिन प्रमुख क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिला, उनमें चोंगकिंग और सिचुआन, गुइझोऊ, शानक्सी, गांसु, युनान और हुबेई के कुछ हिस्से शामिल थे। इन क्षेत्रों में भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, रक्षा निर्माण, रेलवे और बिजली के बुनियादी ढांचे के रूप में भारी निवेश प्राप्त हुआ। पांडेहीआ जैसे पूरी तरह से नए औद्योगिक शहर बिल्कुल शुरू से विकसित हुए, जबकि चोंगकिंग, चेंग्दू, गुइयांग और शीआन जैसे मौजूदा शहरों का काफी विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया। इसने चोंगकिंग के दीर्घकालिक औद्योगिक आधार की नींव रखी। आज, चोंगकिंग पश्चिमी चीन की सबसे मजबूत और सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। \$440 बिलियन से अधिक की वार्षिक GDP के साथ, यह देश की सबसे बड़ी नगरपालिका अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस

शहर का औद्योगिक आधार काफी विविध है, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और लैपटॉप उत्पादन, सेमीकंडक्टर, उपकरण निर्माण और रसायन उद्योगों में मजबूत है। यांग्ची नदी आर्थिक बेल्ट और बहुचर्चित 'बेल्ट एंड रोड पहल' के संगम पर रणनीतिक रूप से स्थित, चोंगकिंग चीन के आंतरिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसका बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क—जिसमें नदी बंदरगाह, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क शामिल है—इसे शेष चीन और उससे आगे के क्षेत्रों से कुशलतापूर्वक जोड़ता है। इस प्रकार, चोंगकिंग की विशाल अर्थव्यवस्था और रणनीतिक आंतरिक स्थान को देखते हुए, चोंगकिंग इंस्ट स्टेशन जैसे हाई-स्पीड रेल संपर्क इसके लोगों और उद्योगों को तटीय बाजारों, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रोबोट्स ने चोंगकिंग इंस्ट रेलवे स्टेशन को इंजीनियरिंग का एक अजूबा कैसे बनाया चोंगकिंग इंस्ट रेलवे स्टेशन को चीन के सबसे तेजी से बढ़ते अंदरूनी बड़े शहरों में से एक की बढ़ती ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था।

व्यूबा में अमेरिका का होगा ईरान वाला हाल, सैन्य कार्रवाई के मूड में ट्रंप ने भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसी देश क्यूबा के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में हैं। उन्होंने क्यूबा की एनजी सप्लाई कार्टेने के बाद अब एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को पूरे कैरियर ग्रुप के साथ तैनात कर दिया है। यह तैनाती उस बेड़े की तरह ही है जिसे उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करने से पहले वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए चारों ओर तैनात किया था। ट्रंप और उनके सहयोगियों ने कहा है कि वे क्यूबा में सत्ता पलटना चाहते हैं। ट्रंप ने इशारों-इशारों में कहा है कि अमेरिका क्यूबा को अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है, "हम वहाँ सत्ता बदलते देखना चाहेंगे।" हालांकि, अमेरिका को डर है कि कहीं वह क्यूबा पर हमला करके ईरान के जैसे फंस न जाए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्यूबा के नेताओं ने टक्कराव से बचने की कोशिश में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत तेज कर दी है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने क्यूबा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने क्यूबा के शक्तिशाली कार्मों परिवार के सदस्य राउल गुइलेर्मो रोड्रिगेज कास्त्रो, साथ ही गृह मंत्री लाजरो अल्वारेज कासास और क्यूबा की खुफिया सेवाओं के प्रमुख के साथ बातचीत की। ट्रंप के निर्देश पर, अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा के बंदरगाहों की घेराबंदी कर दी है, जिससे यह देश गहरे ऊर्जा संकट में फंस गया है। आपूर्ति कम होने के कारण, क्यूबा को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवा जैसी जरूरी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के साथ ही, क्यूबा के आसपास सैन्य विमानों और ड्रोन की उड़ानों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह की हवाई गतिविधियों में बढ़ोतरी को अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि किसी सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है। इस बीच अमेरिकी इंटरलिजेंस कम्यूनिटी इस बात का विश्लेषण कर रही है कि क्यूबा किसी सैन्य कार्रवाई पर कैसी प्रतिक्रिया दे सकता है। इस महीने की शुरुआत में, जब अमेरिकीइंटरलिजेंस कम्यूनिटी 'यूनिवर्सल' नाम के एक प्रतिबंधित, रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर नजर रख रही थी, जो क्यूबा जा रहा था, तो पेंटागन और डिफेंस इंटरलिजेंस एजेंसी (जो अमेरिकी सेना की इंटरलिजेंस शाखा है) के विश्लेषकों ने इस बात का विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि कैरिबियन देश पर किसी अमेरिकी हमले की स्थिति में क्यूबा की क्या



प्रतिक्रिया होगी। इस तरह के इंटरलिजेंस पूर्वानुमान न केवल किसी अमेरिकी कार्रवाई के तत्काल परिणामों को दिखाने का प्रयास करते हैं, बल्कि उसके बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को भी दर्शाते हैं। अमेरिकी सैन्य योजनाकार अक्सर राष्ट्रपति के विचारार्थ विकल्पों को तैयार करते समय इस तरह के विश्लेषणों को शामिल करते हैं। बुधवार को जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा कि क्या क्यूबा के पूर्व नेता राउल कास्त्रो पर अमेरिका के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद क्यूबा में तनाव और बढ़ेगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "नहीं, तनाव नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है।" क्यूबा ने हाल में ही किसी अनाम देश से हमलावर ड्रोन हासिल कर लिए हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वे ड्रोन किसने उपलब्ध कराए हैं या उन्हें किस माध्यम से प्राप्त किया गया है। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल कर लिए हैं। उसने इन ड्रोनों का उपयोग करके ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला करने की योजनाओं पर चर्चा भी की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कनेले ने इस बात से इनकार किया कि उनका देश अमेरिका के लिए किसी भी प्रकार का सैन्य खतरा उत्पन्न करता है, लेकिन उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो उसका परिणाम "रक्तपात" के रूप

में सामने आएगा। इस साल की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने दावा किया था कि क्यूबा में रूस का सबसे बड़ा विदेशी जासूसी केंद्र मौजूद है। बाइडेन प्रशासन ने चीन पर भी आरोप लगाया था कि उसने अमेरिका के तटों से सिर्फ 90 मील दूर स्थित इस कम्यूनिस्ट द्वीप पर जासूसी केंद्र खोल रखे हैं। अप्रैल में, एक प्रतिनिधिमंडल हवाना गया था और उसने क्यूबा को 'स्टारलिनक' (Starlink) सेवा देने का प्रस्ताव रखा था; यह एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जिसे एलन मस्क की कंपनी SpaceX चलाती है। हाल ही में, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देने के अमेरिका के प्रस्ताव को फिर से दोहराया। यह सहायता क्यूबा में धार्मिक संस्थाओं के जरिए भेजी जानी थी, जिसके बारे में उन्होंने पहले कहा था कि क्यूबा सरकार के अधिकारियों ने इस रोक रखा है। विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि क्यूबा में अमेरिका के 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) माइकल हैमर ने हाल के दिनों में क्यूबा के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव की शर्तें बताईं, जिसमें पूरे द्वीप में बांटने के लिए भोजन, दवाएं, सोलर लैंप और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की सरवत नाकेबंदी, फिर भी सुरक्षित निकल रहे भारतीय जहाज



एजेंसी तेहरान

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सख्त नाकाबंदी कर रखी है। इसके बावजूद अब तक भारतीय झंडे वाले 13 जहाज देश के अलग-अलग बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के झंडे वाले जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर सकें। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय झंडे वाले जहाज ईरान की लागू की गई मंजूरी प्रक्रिया के बाद ही होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर रहे हैं। जहाज तभी आगे बढ़ते हैं जब भारत, ईरानी अधिकारियों और भारतीय नौसेना के बीच तालमेल बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधने के लिए भारत तेहरान स्थित अपने दूतावास का इस्तेमाल करता है। इनमें इस्तामिक रिगोव्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और भारतीय नौसेना शामिल हैं। ईरानी अधिकारी उन जहाजों की जांच-पड़ताल करते हैं जिन्हें भारत खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता है। एक बार मंजूरी मिल जाने पर, जहाज के कप्तानों को पालन करने के लिए एक मार्ग (रूट) दिया जाता है और वे ईरानी नौसेना के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। जहाजों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने लोकेशन ट्रांसपॉंडर बंद रखें और सैटेलाइट कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल न करें। ईरान से अनुमति मिलने के बाद, भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय झंडे वाले जहाजों के कप्तानों से सीधे संपर्क करती है और उन्हें मार्ग-बिंदु (वेपॉइंट्स) उपलब्ध कराती है। भारतीय शिपिंग उद्योग के एक सूत्र ने बताया कि भारतीय नौसेना ने उन्हें

निर्देश दिया है कि यदि ईरानी अधिकारी उन्हें रुकने को कहें तो वे रुक जाएं, और यदि आगे बढ़ने का निर्देश दें तो वे आगे बढ़ें। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी ने आगे बताया कि कप्तानों को सख्ती से यह हिदायत दी गई है कि वे दिए गए मार्ग का ही पालन करें। ये इंतजाम उस व्यापक व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसे ईरान ने इस जलडमरूमध्य से जहाजों को गुजरने की मंजूरी देने के लिए स्थापित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने के लिए अलग-अलग देश अनुमति का अनुरोध करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री से संपर्क करते हैं। इन अनुरोधों को 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' को बढ़ा दिया जाता है। इस परिषद में IRGC के सदस्य और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत जैसे देश ने इस संदर्भ में कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। इस मार्ग में किसी भी भू-राजनीतिक तनाव या रुकावट से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते अपने कुल तेल का लगभग 88 प्रतिशत और अयतुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत जैसे देश ने इस संदर्भ में कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। इस मार्ग में किसी भी भू-राजनीतिक तनाव या रुकावट से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते अपने कुल तेल का लगभग 88 प्रतिशत और अयतुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत जैसे देश ने इस संदर्भ में कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। इस मार्ग में किसी भी भू-राजनीतिक तनाव या रुकावट से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं।



अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा- ड्रोन, मिसाइल... अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से सैन्य ताकत बढ़ रहा है ईरान

एजेंसी तेहरान

ईरान ने अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए छह हफ्ते के सीजफायर के दौरान अपने कुछ ड्रोन का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। यह इस बात का एक संकेत है कि वह उन कुछ मिलिट्री क्षमताओं को तेजी से फिर से हासिल कर रहा है, जो अमेरिका-इजरायल के हमलों से कमजोर पड़ गई थीं। इस बीच अमेरिकी इंटरलिजेंस ने बताया है कि ईरान की सेना शुरू में लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को फिर से संगठित कर रही है। CNN ने अमेरिकी इंटरलिजेंस से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि मिलिट्री क्षमताओं को फिर से बनाने का मतलब है - मौजूदा संघर्ष के दौरान नष्ट हुई मिसाइल साइटों, लॉन्चरों और प्रमुख हथियार प्रणालियों की उत्पादन क्षमता को बदलना। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बमबारी का अभियान फिर से शुरू करते हैं, तो ईरान क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। यह उन दावों पर भी सवाल उठाता है कि अमेरिका-इजरायल के हमलों ने लंबे समय में

ईरान की सेना को किस हद तक कमजोर किया है। हालांकि अलग-अलग हथियारों के पुर्जों का उत्पादन फिर से शुरू करने में लगने वाला समय अलग-अलग होता है, लेकिन अमेरिकी इंटरलिजेंस के कुछ अनुमानों से पता चलता है कि ईरान अपनी ड्रोन हमले की क्षमता को महज छह महीनों में पूरी तरह से फिर से हासिल कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "ईरानियों ने उन सभी समय-सीमाओं को पार कर दिया है, जो इंटरलिजेंस कम्यूनिटी ने उनके फिर से संगठित होने के लिए तय की थीं।" ड्रोन हमले क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए विशेष चिंता का विषय है। ईरान ने अमेरिकी इंटरलिजेंस से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि मिलिट्री क्षमताओं को फिर से बनाने का मतलब है - मौजूदा संघर्ष के दौरान नष्ट हुई मिसाइल साइटों, लॉन्चरों और प्रमुख हथियार प्रणालियों की उत्पादन क्षमता को बदलना। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बमबारी का अभियान फिर से शुरू करते हैं, तो ईरान क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा। यह उन दावों पर भी सवाल उठाता है कि अमेरिका-इजरायल के हमलों ने लंबे समय में

कारणों के मेल की वजह से उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को फिर से बनाने में कामयाब रहा है। इन कारणों में रूस और चीन से मिल रहा समर्थन भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और इजरायल ने ईरान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया, जितनी इन दोनों देशों ने उम्मीद की थी। US इंटरलिजेंस के आकलन से परिचित सूत्रों ने बताया कि चीन ने संघर्ष के दौरान भी ईरान को ऐसे पुर्जे देना जारी रखा है, जिनका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में किया जा सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते CBS को बताया कि चीन ईरान को मिसाइल बनाने के पुर्जे दे रहा है, लेकिन उन्होंने इस बारे में और ज्यादा विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आरोप से इनकार करते हुए इसे "तथ्यों पर आधारित नहीं" बताया। इस बीच, हालिया अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार, अमेरिका-इजरायल के हमलों से गंभीर नुकसान पहुंचने के बावजूद ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक-मिसाइल, ड्रोन-हमले और हवाई-रक्षा क्षमताएं मौजूद हैं।





पांच बार की चैंपियन चेन्नई प्लेऑफ रेस से बाहर: गुजरात ने 89 रन से हराया, सुदर्शन, गिल और बटलर के अर्धशतक, तीन गेंदबाजों को 3-3 विकेट

एजेंसी अहमदाबाद

IPL में गुजरात को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इस हार के साथ पांच बार की चैंपियन चेन्नई का इस सीजन का सफर खत्म हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑलआउट हो गई। चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड ने तेज 16 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद सिरान ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। सिरान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट झटकें। मैथ्यू शॉर्ट ने 24 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 47 रन की पारी खेलकर कुछ देर मुक़ाबले में टीम की वापसी कराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंशुल कंबोज ने भी 8 गेंदों में



19 रन बनाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। गुजरात की ओर से कगिसो रबाडा और राशिद खान ने भी 3-3 विकेट लिए। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी

खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान शुभमन गिल ने भी 37 गेंदों में 64 रन बनाए और दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। आखिरी ओवरों में जोस बटलर ने 27 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोके। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए। चेन्नई की ओर से मुकेश कुमार, स्पेंसर जॉन्सन और अंशुल कंबोज को 1-1 विकेट मिला। दोनों टीमों को प्लेइंग-11 गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंघु, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिरान। चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉन्सन, मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह।

खेलों में डोपिंग का खेल खत्म! अब कोच, डॉक्टर और सप्लायर्स पर भी गिरेगी गाज, नया विल तैयार

एजेंसी नई दिल्ली

भारत सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम में महत्वपूर्ण विधायी बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत प्रतिस्पर्धी एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी या वितरण करने वाले व्यक्तियों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है। आगामी संशोधन का उद्देश्य अवैध वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जिसके तहत इन प्रतिबंधित पदार्थों को जानबूझकर निर्धारित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें चिकित्सक भी शामिल हैं, को पांच साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। खेल मंत्रालय ने 18 जून की अंतिम समय सीमा से पहले जनता से आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किए हैं। यह विधेयक अगले संसदीय सत्र के दौरान संसदों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि जो कोई भी खेल में डोपिंग के उद्देश्य से या उससे संबंधित किसी भी उद्देश्य से किसी एथलीट को डोपिंग की



अनुमति देता है या उससे संपर्क करता है... उसे पांच वर्ष तक के कारावास या दो लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया

कि डोपिंग विरोधी नियमों का दायरा केवल खिलाड़ियों तक ही सीमित न रहकर उन सहायक कर्मचारियों तक भी विस्तारित होना चाहिए जो अवैध प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों तक पहुंच को सुगम बनाते हैं। मांडविया ने तत्काल विधायी बदलाव के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि डोपिंग अब केवल खेल उल्लंघन नहीं रह गया है; यह खिलाड़ियों का शोषण करने वाले एक संगठित तंत्र में तब्दील हो गया है। मंत्री ने आगे कहा कि हम केवल सेवन करने वालों को ही दंडित करते हैं, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भी निशाना बनाना आवश्यक है। इसलिए, चाहे वह कोच हो, प्रबंधक हो, साथी खिलाड़ी हो या कोई भी व्यक्ति जिसकी खिलाड़ी तक सीधी पहुंच हो, आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा पाए जाने वाले सभी लोगों पर इन संशोधनों के पारित होने पर मुकदमा चलाया जाएगा।

22 साल का इंतजार खत्म! ईस्ट बंगाल ने जीता बड़ा फुटबॉल खिताब, कोलकाता में जश्न का माहौल



एजेंसी नई दिल्ली

कोलकाता में बुधवार की रात भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक यादगार पल बन गई है। करीब 22 साल के लंबे इंतजार, निराशा और संघर्ष के बाद ईस्ट बंगाल ने आखिरकार बड़ा भारतीय फुटबॉल खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने इंटर काशी एफसी को 2-1 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि पिछले दो दशकों में ईस्ट बंगाल कई बार खिताब के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार टीम को निराशा हाथ लगी थी। इस दौरान क्लब को खराब प्रबंधन, आर्थिक चुनौतियों और शीर्ष स्तर पर बने रहने की लड़ाई तक का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार टीम ने पूरे सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरकार अपने समर्थकों का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, कोलकाता में खेले गए मुक़ाबले में ईस्ट बंगाल की ओर से स्टार स्ट्राइकर यूसेफ एबेजारी और फ्लिस्तीनी मिडफील्डर मोहम्मद राशिद ने गोल दागे हैं। दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाने में महत्व भूमिका निभाई है। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद हजारों समर्थकों ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। बता दें कि इस खिताबी दौड़ का सबसे रोमांचक पहलू यह रहा कि ईस्ट बंगाल ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मोहन बागान सुपर जायंट को

पीछे छोड़ते हुए टॉफी जीती है। मोहन बागान ने अपने मुक़ाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को 2-1 से हराया था और टीम को खिताब की उम्मीद थी। हालांकि गोल अंतर के आधार पर ईस्ट बंगाल आगे निकल गया और टॉफी उसके नाम हो गई। इस सीजन का अंतिम दिन भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहा है। अंतिम दौर में चार टीमों खिताब की दौड़ में बनी हुई थी। ईस्ट बंगाल अंक तालिका में शीर्ष पर था, जबकि मोहन बागान सुपर जायंट उसके बेहद करीब मौजूद था। इसके अलावा मुंबई सिटी एफसी और पंजाब एफसी की टीमों भी खिताब जीतने की उम्मीद बनाए हुए थी। वहीं जमशेदपुर एफसी के पास भी गणितिय संभावना बची हुई थी। गौरतलब है कि ईस्ट बंगाल की इस जीत को सिर्फ एक टॉफी नहीं बल्कि क्लब के पुनर्जन्म के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से संघर्ष कर रही इस टीम ने आखिरकार अपने समर्थकों को खुशी का बड़ा मौका दिया है। शोशल मीडिया से लेकर कोलकाता की सड़कों तक जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। फुटबॉल विश्वभरों का मानना है कि इस खिताब से भारतीय फुटबॉल में पुरानी प्रतिद्वंद्विता को नई ऊर्जा मिलेगी। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच मुक़ाबलों की हमेशा से भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा माना जाता रहा है और इस बार की खिताबी जंग ने इस और भी खास बना दिया।

सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, टी20 में 200 छक्के भी पूरे हुए, शुभमन गिल ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई

एजेंसी नई दिल्ली

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 64 रनों की पारी खेली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सलामी बल्लेबाज करने उतरे गिल ने सिर्फ 37 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के मारे। स्पेंसर जॉन्सन ने उनका विकेट लिया। अपनी इस पारी में गिल ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए, चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने कप्तान के रूप में 55 मैचों में 1871 रन बनाए। 47 पारियों में गिल के 1934 रन हो गए हैं। टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल के 6000 रन भी हो गए हैं। 2018 में गिल ने आईपीएल से ही डेब्यू किया था। केकेआर के लिए उन्होंने अपना पहला मैच खेला



था। 189 मैचों में गिल 6000 रनों तक पहुंचे हैं। शुभमन गिल टी20 क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। 185 पारियों में

उन्होंने यह कारनामा किया है। केएल राहुल ने 1666 और विराट कोहली ने 184 पारियों में 6000 रन बनाए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच इस मुक़ाबले में 125 रनों की साझेदारी हुई। दोनों एक साथ 46वां बार बैटिंग कर रहे थे। दोनों के बीच 10वीं हजारां साझेदारी है। यह टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड भी है। क्रिस गेल-विराट कोहली के साथ ही बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान और एबी डिविलियर्स-विराट कोहली ने भी 10-10 बार टी20 में शतकीय साझेदारी की है। शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में अपने 200 छक्के पूरे कर लिए हैं। यह उनका 188वां मुक़ाबला है। इस मैच से पहले उनके 198 छक्के थे। तीन छक्कों की मदद से वह 201 छक्कों तक पहुंच गए हैं।

व्यापार

मिडिल ईस्ट से फंसी सप्लाई तो चीन चट्टानों को चीरकर निकालने लगा गैस

एजेंसी नई दिल्ली

चीन अपनी जिद के लिए जाना जाता है। वही फिर दिखाई दिया है। अपने विशाल कोयला भंडारों से हजारों मीटर नीचे वह एक ऐसे गैर-पारंपरिक ईंधन स्रोत का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। इसका मकसद नैचुरल गैस की नई सप्लाई शुरू करना है। साथ ही ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के बीजिंग के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। मिडिल ईस्ट से गैस सप्लाई बाधित होने के बीच उसने गहरी कोयला चट्टानों से गैस निकालने पर फोकस बढ़ाया है। ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी दिग्गज कंपनी पेट्रोचाइना के विशेषज्ञों का अनुमान है कि कंपनी 2035 तक 30 अरब क्यूबिक मीटर (1.06 ट्रिलियन क्यूबिक फीट) 'कोल रॉक गैस' यानी सीआरजी का उत्पादन कर सकती है। यह पिछले साल के रिकॉर्ड शेल गैस उत्पादन से भी ज्यादा होगा, जो देश के कुल उत्पादन का 10% था। क्या है चीन की चाहत? 'कोल रॉक गैस' को विकसित करने की पहल बीजिंग के बड़े प्रयास का हिस्सा है। इसके तहत वह अपने ऊर्जा स्रोतों में डायवर्सिफिकेशन लाना चाहता है। आयात पर अपनी निर्भरता कम करना इसके पीछे मंशा है। इस स्ट्रेटेजी के साथ ही चीन की ओर से अपने वाहनों के बेड़े का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन करने के कारण वह दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक होने के बावजूद ईंधन युद्ध से पैदा हुई गंभीर बाधाओं से काफी हद तक सुरक्षित रहा है। इस खास तकनीक से निकलती है गैस सीआरजी निकालने के लिए हॉरिजेंटल ड्रिलिंग और 'फ्रैकिंग' तकनीक की जरूरत होती है। इसका अभी केवल चीन में ही व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे पेट्रोचाइना ने एक दशक से भी ज्यादा समय तक शेल गैस विकसित करते हुए और भी बेहतर बनाया है। यह देश की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी है। यह गैस मुख्य रूप से 'ऑर्डोस बेसिन' में पाई जाती है, जो तीन प्रांतों तक फैला हुआ है। कंपनी इसे आगे चरण का रणनीतिक ईंधन कहती है। यह देश के



गैस उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा बन सकता है। S&P ग्लोबल एनर्जी के प्रिंसिपल गैस एनालिस्ट हुआंग तियानशी ने कहा, 'सीआरजी में इस समय धरोरू स्तर पर उपलब्ध गैस के अन्य स्रोतों को तुलना में विकास की कहीं ज्यादा क्षमता मौजूद है।' चीन ला सकता है बहुत बड़ा बदलाव विश्वभरों के अनुसार, चीन दुनिया में गैस का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अनुमान है कि 2040 के आसपास इसकी सालाना बढ़त अपने चरम पर पहुंच जाएगी। यह अभी के 430 अरब क्यूबिक मीटर (bcm) से बढ़कर 600 से 650 bcm तक हो सकती है। शेल गैस और पारंपरिक गैस संसाधनों के उत्पादन में आ रही गिरावट की भरपाई के लिए किसी बड़े नए स्रोत का सफलतापूर्वक दोहन करने से चीन की

कहा, 'पिछले पांच सालों में दुनिया भर में बार-बार होने वाली और गंभीर भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने यह साफ कर दिया है कि स्थिर आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए सप्लाई की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करना चीन के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली रणनीतिक प्राथमिकता बनी रहेगी।' पेट्रोचाइना के नेतृत्व में चीन की सरकारी तेल-गैस कंपनियों ने दशकों तक 'कोलबेड मीथेन' का उत्पादन करके 'कोल रॉक गैस' की तकनीक विकसित की है। कोलबेड मीथेन कोयला खदानों की ऊपरी परतों में पाया जाता है। हालांकि, कोलबेड मीथेन ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कारण है कि इसकी लागत बहुत ज्यादा है और हर कुर्र से उत्पादन बहुत कम होता है। चीन के कुल गैस उत्पादन में इसका योगदान सिर्फ 5% है। लेकिन, जैसे-जैसे पेट्रोचाइना ने और

गर्हाई तक खुदाई की, उसने 2021 में 'हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग' (जिसे 'फ्रैकिंग' भी कहते हैं) नाम की 'शेल गैस' तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह तकनीक उसने ओर्डोस बेसिन के दाजी क्षेत्र में स्थित 'जिशन 6-7' कुर्र पर अपनाई। यहाँ उसने जमीन की सतह से 2,200 मीटर नीचे मौजूद चट्टानों में 3,000 मीटर (9,843 फीट) गहरा एक हॉरिजेंटल कुआँ खोदा। फ्रैकिंग तकनीक में पानी, रेत और रसायनों को बहुत ज़्यादा दबाव के साथ जमीन में डाला जाता है। यही वह तकनीक है जिसने अमेरिका में 'शेल तेल और गैस' के उत्पादन में जबरदस्त तेजी ला दी थी। इस तकनीक की मदद से दाजी क्षेत्र में गैस का एक ऐसा भंडार मिला, जिससे हर रोज 1,00,000 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। इस सफलता के बाद खुदाई का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। रॉयटर्स ने बताया कि 'चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प' (CNPC) के 2025 में बीजिंग में हुए एक सेमिनार प्रजेंटेशन के अनुसार, वह अनुमान लगाया गया है कि चीन के 14 कोयला बेसिनों में 6,000 मीटर तक की गहराई वाली चट्टानों में 13 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर (tcm) गैस के ऐसे भंडार मौजूद हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से निकाला जा सकता है। सीएनपीसी ही पेट्रोचाइना की मूल कंपनी है। पिछले साल के अंत तक चीन ने 700 से ज्यादा 'कोल रॉक गैस' कुर्र खोद लिए थे। 2025 में कुल 4.2 bcm गैस का उत्पादन किया था। इसमें से ज्यादातर गैस दाजी क्षेत्र से ही मिली थी। सीएनपीसी के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सीनियर जियोलॉजिस्ट झांग जुनफेंग ने रॉयटर्स को बताया, 'चीन पहला और एकमात्र ऐसा देश है जो CRG को कमर्शियल तौर पर डेवलप कर रहा है। ऐसा देश की अनेक जियोलॉजी के कारण है। इसके पारंपरिक कोल सीम गैस डेवलपमेंट की क्षमता अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है।' सीएनपीसी के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोचाइना को पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बोवें बेसिन में खोद गए दो जंघ कुआँ में भी सीआरजी से भरपूर परतें मिलीं। यहाँ कंपनी कोल सीम गैस का उत्पादन कर रही है। अपनी इस सफलता को दुनिया भर में दोहराने की उम्मीद कर रही है।

आईपीओ लिस्टिंग के बड़े नियम बदलने की तैयारी में सेबी, "मूल्य खोज" पर होगा फोकस

एजेंसी नई दिल्ली



शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आने वाले समय में नियम बदल सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी ने आईपीओ और दोबारा सूचीबद्ध होने वाले शेयरों की शुरुआती ट्रेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला किया है। नियामक का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था कई बार शेयरों की सही कीमत तय होने में बाधा बन रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार सेबी ने इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है और बाजार सहभागियों से सुझाव मांगे हैं। यह प्रस्ताव खासतौर पर लिस्टिंग वाले

दिन होने वाले प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत आईपीओ और दोबारा सूचीबद्ध होने वाले शेयरों में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे का प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र चलता है। इस दौरान केवल सीमित मूल्य वाले आदेश लगाए जा सकते हैं, जबकि बाजार मूल्य वाले आदेशों की अनुमति नहीं होती है। सेबी ने कहा है कि बाजार से मिले सुझावों में यह बात सामने आई कि मौजूदा डमी प्राइस बैंड और आधार मूल्य तय करने की प्रक्रिया कई मामलों में कीमतों को कुचिन्न रूप से दबा रही है। इसके कारण सामान्य ट्रेडिंग शुरू होने के बाद शेयरों में अचानक तेज खरीदारी दबाव बन जाता है और कई बार ऊपरी सर्किट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

बताया जा रहा है कि एक मामले में प्री-ओपन सत्र के दौरान लगभग 90 प्रतिशत खरीद आदेश केवल इसलिए खारिज हो गए क्योंकि वे तय मूल्य सीमा से बाहर थे। सेबी का मानना है कि ऐसी स्थिति बाजार में वास्तविक मांग और सही मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार आईपीओ वाले शेयरों के लिए डमी प्राइस बैंड आधार मूल्य से 50 प्रतिशत नीचे और 100 प्रतिशत ऊपर तक रखा जाता है। वहीं दोबारा सूचीबद्ध होने वाले शेयरों के लिए यह सीमा 85 प्रतिशत नीचे और 50 प्रतिशत ऊपर तक होती है। छोटे और मध्यम उद्योग वर्ग के आईपीओ के लिए यह दायरा 90 प्रतिशत ऊपर और नीचे तक निर्धारित है।

एक महीने तक बिहार के राजगीर में एक भी कौआ नजर नहीं आता, सतयुग से कलयुग तक बना हुआ है रूठने का रहस्य



अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है जिसे भगवान विष्णु की आराधना के लिए उत्तम मास माना जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है जिसके दौरान मांगलिक और नए कार्य करने वर्जित माने गए हैं। इस माह में बिहार के राजगीर में मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। यहां सतयुग से लेकर कलयुग तक कौए के रूठने का रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि यहां पूरे मलमास की अवधि के दौरान एक भी कौआ नजर नहीं आता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए पं. राकेश झा से विस्तार से जानें क्यों राजगीर में एक भी कौआ नहीं आता नजर और क्या है काले काग के रूठने की वजह। बिहार के इस स्थान पर 1 महीने तक नहीं दिखते कौए बिहार के राजगीर से जुड़ी एक बहुत ही खास बात है कि यहां पूरे मलमास की अवधि में एक भी कौआ नजर नहीं आता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। मान्यता है कि

एक बार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा वसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में यज्ञ आयोजित किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी 33 करोड़ देवी और देवताओं को आमंत्रित किया था। ऐसे में सभी उस यज्ञ में पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां काले काग यानी कौए को राजा वसु बुलाना भूल गए थे। इस बात से वो रुष्ट हो गए और पूरे मलमास के दौरान राजगीर में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से मलमास के दौरान एक भी कौआ बिहार के राजगीर में नहीं दिखाई देता है। सतयुग से कलयुग तक कौए के रूठने का रहस्य बना हुआ है। राजगीर में कौए से जुड़ा तो रहस्य बना ही हुआ है, वहीं, यहां पर मौजूद कुंड की भी विशेष मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार राजगीर में यज्ञ के लिए ब्रह्माजी ने 22 कुंड और 52 जल धाराओं का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यज्ञ के दौरान जब देवी-देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी उठानी

पड़ रही थी तभी इन कुंडों का ब्रह्मा जी ने निर्माण करवाया था। वैभागीर पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच में कई झरने हैं जिनका जल गर्म रहता है। यहां सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। इनमें से ब्रह्मकुंड का अत्यधिक महत्व बताया गया है जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। यहां के कुंड में स्नान करने से कटते हैं सारे पाप मान्यता है कि मलमास मेले के दौरान यहां 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। साथ ही, इस स्थान शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णुजी की पूजा की जाती है। यही कारण है कि राजगीर में मलमास मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे में दूर-दूर से श्रद्धालु राजगीर के कुंडों में पवित्र स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि राजगीर के इन कुंडों में मलमास के दौरान स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। साथ ही, यहां पूजा, दान-पुण्य आदि कार्य करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है।

25 मई से 2 जून तक खूब तपेगी धरती, 9 दिन पड़ती है भीषण गर्मी



गर्मी अब और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, नई दिल्ली में मंगलवार को तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि, ये तपन अभी रुकने वाली नहीं है। दिल्ली-पनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ेगा। भारत सरकार ने हीटवेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी और भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना है। 'नौतपा' का अर्थ है नौ दिनों की भारी तपिश। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और तेजी से पड़ती हैं, जिससे गर्मी बेहद बढ़ जाती है। इन नौ दिनों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहता है और लू का प्रकोप देखने को मिलता है। हालांकि, नौतपा सिर्फ गर्मी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मानसून और कृषि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जितनी भीषण गर्मी और सूखा नौतपा के दौरान पड़ेगा, मानसून उतना ही अच्छा और लंबा होने की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा के गर्म और शुष्क दिन समुद्र के पानी को गर्म करते हैं, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है और खरीफ फसलों को अच्छी बारिश मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। सूर्य की तेज उपस्थिति में चंद्रमा की

शीतलता कम हो जाती है, इसलिए इन दिनों गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहता है। धर्म शास्त्रों में सलाह मिलती है कि नौतपा के दौरान क्या करें और क्या न करें। नौतपा के दौरान सूर्य देव की उपासना करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में चावल, गुड़, रोली व लाल फूल डालकर अर्पित करें व धूप-दीप दिखाएं। नौतपा में पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य का भी काफी महत्व है। भीषण गर्मी के 9 दिनों के दौरान जरूरतमंदों को शरबत, सत्तू, ठंडा पानी, पंखा और मौसमी सब्जियां व फल दान करें। भारी या बासी भोजन को त्यागकर जितना हो सके सात्विक और ताजा भोजन करें। इस दौरान लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। पीसा लगाना, पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना भी पुण्यदायी होता है। पुण्य कामों को करने के साथ ही कुछ कामों को नौतपा के दौरान नहीं करने की सलाह भी मिलती है। नौतपा में विवाह, समाई, मुंडन, गृह प्रवेश, समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। कोई नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से भी बचना चाहिए। दोपहर में घर से बाहर निकलने से परहेज करने के साथ लंबी यात्राएं टालें क्योंकि यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। यही नहीं दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर कर्तई न निकलें। इस दौरान खूब पानी पिएं, छाता और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें।

कुंडली में शनि, राहु-केतु हैं भारी तो गंगा दशहरा पर करें ये उपाय

सनातन धर्म में मां गंगा को पवित्र और अमृत के समान माना गया है। गंगा दशहरा का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ ज्योतिषीय दोषों को शांत करने के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। अगर आप लंबे समय तक शनि की साढ़ेसाती, डैय्या या राहु-केतु के बुरे प्रभावों से परेशान रहते हैं, तो गंगाजल आपको इन सभी समस्याओं को दूर करेगा।

शनि दोष से मिलेगी राहत - अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है या आर्थिक उन्नति रुकी हुई है, तो गंगा दशहरा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर एक लोटे में गंगाजल लें, उसमें थोड़ा-सा काला तिल और कच्चा दूध मिलाएं। इसे पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से शनि की साढ़ेसाती और डैय्या का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। आपके घर के पास शनि मंदिर है, तो गंगा दशहरा के दिन वहां जाकर गंगाजल में सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर और शनि देव की मूर्ति पर अर्पित करें। इस उपाय के करने से शनि से संबंधित कष्ट दूर हो जायेंगे। गंगा दशहरा पर सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से शनि के कारण आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होते हैं। राहु और केतु दोष को शांत करने की तरीके कुंडली में राहु-केतु दोष होने पर जीवन में अचानक से मानसिक तनाव, डर और गृह क्लेश उत्पन्न करता है। इन्हें शांत करने के लिए गंगा दशहरा पर गंगाजल का उपाय कर सकते हैं- राहु और केतु के दोषों को दूर करने के लिए आप गंगा दशहरा पर श्रद्धा के अनुसार, तांबे या चांदी के लोटे में गंगाजल भरें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो निराश न हों। अपने घर पर ही सामान्य स्नान के पानी में थोड़ा-सा गंगाजल मिला लें और स्नान करें। ऐसा करने से राहु के कारण होने वाला मानसिक भ्रम और अज्ञात डर दूर हो जाता है। राहु-केतु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। हर एक कमरे में गंगाजल छिड़कें, जहां अंधेरा रहता हो या नकारात्मक ऊर्जा जल्दी जमा होती है। गंगा दशहरा पर ध्यान रखें ये जरूरी बातें इन उपायों का पूरा फल तबभी मिलता है जब इनको सही नियम और सेवा भाव से किया



जाएँ। कोई उपाय तभी कारगर होता है, जब आप उसे साफ मन से करें। कोई भी धार्मिक कार्य करते समय पूर्ण श्रद्धा रखें, किसी के प्रति गुस्सा न करें और न ही किसी को अपशब्द बोलें।

गंगा दशहरा पर गंगाजल के उपायों के साथ-साथ किसी जरूरतमंदों व्यक्ति को काले तिल, छाता, हाथ का पंखा या मौसमी फल दान कर सकते हैं, ऐसा करने से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी।

आज का राशिफल: वृषभ, सिंह के लिए खुलेंगे कमाई के नए रास्ते, फायदा होगा

मेष राशि पैसों को लेकर सोच में स्पष्टता रहने वाली है। वृषभ राशि में सूर्यदेव और बुधदेव मौजूद हैं। इनकी कृपा से आज आप पैसों से जुड़े बड़े निर्णय आसानी से ले पाएंगे। कोई भी खर्च करने से पहले गहराई से विचार करें। यह विचार आपको बचत को मजबूत करेगा। ग्यारहवें भाव में राहु मौजूद है। इससे आपके नेटवर्क और बिजनेस के जरिए धन लाभ होगा। हालांकि, आज परिवार की जरूरतों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। भविष्य की सुरक्षा के लिए अभी से बचत बनाकर चलें।

वृषभ राशि आज आपके दूसरे भाव में शुक्रदेव और गुरुदेव की युति बनी हुई है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती देने वाली है। इस दौरान आपका पूरा ध्यान सुरक्षित निवेश और बचत पर रहेगा। राहु की शुभ स्थिति के चलते आपको नौकरी या बिजनेस से बेहद धन लाभ हो सकता है। हालांकि, बारहवें भाव में केतु मंगलदेव आपके परेशान कर सकते हैं। वे अचानक फालतू की चीजों पर पैसा खर्च करा सकते हैं। इसलिए आज किसी भी तरह के जल्दबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। मिथुन राशि आज चंद्रदेव कर्क राशि में मौजूद हैं। यह आपकी आर्थिक प्लानिंग को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन सुझाव देगा। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव की उपस्थिति बनी हुई है। इससे आपके टीम वर्क या पार्टनरशिप के जरिए अच्छा मुनाफा मिल सकता है। विदेशी संबंधों या यात्राओं से भी धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि, सूर्यदेव के प्रभाव के कारण मन में कुछ अनजाना डर हो सकता है। इससे जल्दबाजी में फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। आज के दिन किसी भी बड़े निवेश को टालना ही समझदारी होगी।

कर्क राशि आज ग्यारहवें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की जुगलबंदी बनी हुई है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को शानदार बनाने वाली है। नौकरीपेशा जातकों को नए लोगों से मिलने का फायदा मिलेगा। इससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। मंगलदेव की कृपा भी आपकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। हालांकि, आठवें भाव का राहु संयुक्त धन को लेकर भी भ्रष्टाचार तनाव पैदा कर सकता है। यह पार्टनरशिप के पैसों में असमंजस ला सकता है। आज यात्रा, सेहत या आध्यात्मिक कार्यों पर धन खर्च होने के योग हैं।

सिंह राशि आज मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में शुक्रदेव और गुरुदेव की युति बनी हुई है। यह आपके लिए पैसों की बरसात करने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों और पेशेवर संपर्कों के



माध्यम से बड़े लाभ की उम्मीद है। दसवें भाव के सूर्यदेव भी करियर में धन लाभ के शानदार अवसर ला रहे हैं। हालांकि, आठवें भाव में बैट शनिदेव आपके चेतावनी दे रहे हैं। वे लोन, कर्ज या टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतने को कहेंगे। दिखावे में आकर बिना सोचे-समझे पैसा उड़ाने से बचें। कन्या राशि आर्थिक दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें भाव के चंद्रदेव आपकी मनी प्लानिंग को सही दिशा देंगे। छठे भाव का राहु कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का पूरा आर्थिक लाभ दिलाएंगे। शुक्र और गुरु की शुभ स्थिति भी बनी हुई है। यह करियर में तरक्की के साथ-साथ धन वृद्धि के नए योग बना रही है। लेकिन, आठवें भाव के मंगलदेव आपको सचेत कर रहे हैं। वे पैसों के मामले में शॉर्टकट न अपनाने की सलाह देते हैं। आज किसी को उधार देने या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना ही बेहतर होगा। तुला राशि छठे भाव में शनिदेव की उपस्थिति मन में कुछ अनजाना डर हो सकता है। इससे जल्दबाजी में फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। आज के दिन किसी भी बड़े निवेश को टालना ही समझदारी होगी।

भरे निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले न लें। परिवार की सुख-सुविधाओं पर कुछ धन खर्च होने के योग हैं। इसलिए हर कदम समझदारी से उठाएं। मकर राशि दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति बनी हुई है। यह आज आपके सामने अचानक धन लाभ के नए अवसर ला सकती है। पांचवें भाव के सूर्य और बुध आपको पैसों से जुड़े सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। यह आपकी सोच में व्यावहारिक स्पष्टता लाएंगे। छठे भाव में शुक्र और गुरु की युति नौकरीपेशा जातकों की आय में वृद्धि के संकेत दे रही है। हालांकि, आज आपको अपने हाथ पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। फालतू की खरीदारी या बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। केवल लॉन्ग-टर्म सुरक्षा पर ध्यान दें। कुंभ राशि दूसरे भाव में शनिदेव की उपस्थिति बनी हुई है। यह आपके पैसों के मामले में बेहद सतर्क और समझदार बनाने वाली है। यह आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा। छठे भाव के चंद्रदेव नौकरी के माध्यम से आपको लाभ कमाने के अवसर देंगे। यह आपको सही निर्णय लेने की समझ देगा। आपकी ही राशि में बैट राहु देव आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका देंगे। नेटवर्किंग से लाभ उठाने के योग बनेंगे। आज अपने निवेशों पर पैनी नजर रखें और सारा ध्यान केवल बचत बढ़ाने पर लाएं। मीन राशि दूसरे भाव में मंगलदेव की उपस्थिति बनी हुई है। यह आज आपको एक बेहतरीन और व्यावहारिक बजट बनाने की प्रेरणा देगी। तीसरे भाव के सूर्यदेव और बुधदेव की कृपा बनी हुई है। इसकी मदद से आज आपकी मार्केटिंग या नेटवर्किंग के जरिए धन लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। बातचीत से भी फायदा होगा। हालांकि, चौथे भाव में शुक्र और गुरु की युति बनी हुई है। इसके कारण आपका मन घर की सुख-सुविधाओं पर फालतू पैसा उड़ाने का कर सकता है। मन पर थोड़ा काबू रखें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

तुलसी को सूखने से बचाने के उपाय, गर्मी में हरी भी रखने के लिए जड़ में डालें दूध

तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर घर के आंगन में तुलसी के पौधा जरूर होती है लेकिन, इस समय बढ़ती गर्मी के कारण यदि आपकी तुलसी का पौधा भी बार बार सूख जाता है तो आपको इसकी विशेष देखभाल करने की जरूरत है। बढ़ते तापमान के कारण तुलसी माता गर्मी में झूलस न जाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें। मान्यता है कि तुलसी की सूखना एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में शास्त्रों से जाने गर्मियों में तुलसी की सेवा कैसे करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस आंगन में तुलसी लगी जाती है वहां रोजाना तुलसी का पूजन जरूर करें। सबसे पहले स्नान करके

तुलसी में जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा पाठ आरंभ करें। तापमान बढ़ने के कारण धूप में तुलसी झूलस जाती है। ऐसे में सूखे नारियल के छिलके तुलसी के गमले में नीचे डाल दें। इसके बाद मिट्टी भरकर तुलसी का पौधा लगाएं। दरअसल, नारियल के छिलका पानी को सूख लेता है जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। तुलसी में सुबह और शाम दोनों समय जल अर्पित करें। तुलसी में जल अर्पित करने के साथ साथ तुलसी की पत्तियों पर भी जल जरूर डालें। इस बात का ख्याल रखें कि आप तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाएं। ऐसा करने से तुलसी के पौधे



में तरावट ज्यादा रहती है। तुलसी माता को गर्मियों में लाल रंग का सूती कपड़ा जरूर उड़ा कर रखें। कपड़ा इस तरह से ओढ़ाएं कि तुलसी माता पर सीधे धूप न लगे। वैसे तो तुलसी की पूजा रोजाना करनी चाहिए। लेकिन, विशेष रूप से गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में कच्चा दूध मिलाकर सिंचाई करें। इस बात का ख्याल रखें कि आप जल में दूध मिलाकर ही तुलसी माता को अर्पित करें सिर्फ दूध अर्पित न करें। तुलसी को पौधा सूखने का संकेत कई बार तुलसी के पौधे की अच्छे से देखरेख करने के बाद ही तुलसी का

पौधा सूख जाता है। अगर देखरेख के बाद भी तुलसी सूख जाती है तो यह भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी को बुध ग्रह से संबंध माना गया है। ऐसे में अगर किसी की कुंडली में बुध शुभ स्थिति में नहीं होते हैं तब भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। अगर बार बार घर में लगी तुलसी सूख जाती है तो यह पितृदोष के कारण भी हो सकता है। अगर अपने नया तुलसी का पौधा लगाया है और लगाने के कुछ ही समय में तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं तो यह भी पितृदोष का कारण हो सकता है।

जल बचाने का संदेश और स्वास्थ्य सेवा का संगम, विक्रमपुर में सजी जनजागरूकता की अनूठी मिसाल पद्मश्री उमाशंकर पाण्डेय ने जल संरक्षण को बताया आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का संकल्प,स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने उठाया लाभ



दैनिक कारखाने का सफर। सारणी

ग्राम पंचायत विक्रमपुर में गुरुवार को ग्राम भारती महिला मंडल के तत्वावधान में जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को समर्पित जल पंचायत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित जल संरक्षण विशेषज्ञ उमाशंकर पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन में जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। देशभर में जल संरक्षण की अलख जगाने वाले पद्मश्री उमाशंकर पाण्डेय आज जल एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रेरणास्रोत बन चुके हैं। बुंदेलखंड के जखनी गांव से शुरू हुआ उनका चर्चित अभियान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ अब देशभर में जल प्रबंधन का सफल मॉडल माना जाता है। उनके प्रयासों से हजारों गांवों में वर्षा जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने जैसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय

द्वारा राष्ट्रीय जल योद्धा सम्मान तथा वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उमाशंकर पाण्डेय ने पानी की पाठशाळा, अटल भूजल यात्रा और जल के लिए चल जैसे अभियानों के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों, किसानों और नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। वर्तमान में वे विभिन्न राष्ट्रीय समितियों एवं संस्थानों के साथ मिलकर जल क्रांति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में अमेय साठे और आशीष तयाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं वंदन के साथ हुआ। ग्राम भारती महिला मंडल की अध्यक्ष भारती अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में उमाशंकर पाण्डेय ने कहा कि जल संरक्षण केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल संरक्षण, पेड़ लगाने और पानी के सदुपयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भी पर्यावरण सुरक्षा और जनसहभागिता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण

जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इस अवसर पर गांव में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। उपस्थित महिलाओं और बच्चों को स्वल्पाहार भी वितरित किया गया। कार्यक्रम को आधिकारिक मोडिया साहेंदर के रूप में का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के CSR अंतर्गत ग्राम पंचायत विक्रमपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में लगभग 100 से 110 ग्रामीण मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। स्वास्थ्य शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी की चिकित्सकीय टीम ने सेवाएं दीं। शिविर में महिलाओं एवं बालिकाओं को सैनिकी पैड वितरित कर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के समापन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को संध्या की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।



तकनीकी क्रांति के जनक राजीव गांधी को कांग्रेस जनों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि दूरसंचार, कंप्यूटर और पंचायती राज की मजबूत नींव रख भारत को आधुनिक युग की ओर ले गए राजीव गांधी

दैनिक कारखाने का सफर। सारणी

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय नाना कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की नई दिशा दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुपति एरोलू एवं भोला कांति ने कहा कि राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा था। उन्होंने देश में दूरसंचार क्रांति की शुरुआत करते हुए गांव-गांव तक संचार सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उठाए गए उनके कदमों ने आज के डिजिटल भारत की मजबूत नींव रखी। कांग्रेस के जनसेवक गोविंदा एरोलू ने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में भारतीय रेलवे में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू हुई, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली। ग्रामीण क्षेत्रों को देश-दुनिया से जोड़ने के लिए पीसीओ बूथों का विस्तार किया गया। वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की स्थापना तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के

माध्यम से दूरसंचार तकनीक को नई गति मिली। नेताओं ने बताया कि राजीव गांधी ने केवल तकनीकी विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक और लोकतांत्रिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ने के उद्देश्य से मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर गांवों तक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ग्रामीण प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। इसके साथ ही पेयजल, टीकाकरण, साक्षरता, डेयरी और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किए गए, जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है। युवा नेता रोहन रघुवंशी ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कार्य किए, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका विजन आज भी देश के विकास की प्रेरणा बना हुआ है। कार्यक्रम में तिरुपति एरोलू, भोला कांति, हेमंत धोते, माणिक थोटे, गौतम नागले, विलास लोनारे, हरीश पाल, सन्नी एरोलू, प्रवीण पाल, गोविंदा एरोलू, तरुण पाल, मणि सुब्रह्मण्यम, आसिफ, विपिन कुशवाह, डी. डी. देशमुख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

तपती धरती, झुलसते दिन बैतूल जिले में 44 डिग्री के करीब पहुंचा पारा नवतपा से पहले ही गर्मी का प्रचंड वार, घरों में कैद होने लगे लोग स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी लू से बचाव की सलाह

दैनिक कारखाने का सफर। सारणी

मई माह के अंतिम दिनों में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाए शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को बैतूल जिले में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचकर 44 डिग्री की छूने की कोशिश करता नजर आया। खास बात यह है कि अभी नवतपा शुरू होने में चार दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित कर दी है। वन संपदा और हरियाली से समृद्ध बैतूल जिला इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। नगर पालिका परिषद सारणी सहित ग्रामीण अंचलों में दोपहर के समय



सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग जल्दी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भी दोपहर के समय चहल-पहल कम नजर आ रही है। भीषण गर्मी का

असर सबसे अधिक बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। दोपहर में चलने वाली तपती हवाएं लोगों को लू का शिकार बना सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान को देखते

हुए विशेष सावधानी बरतना जरूरी हो गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ और ओआरएस का सेवन करें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें तथा सिर को गमछे या टोपी से ढंककर रखें। बाहर निकलते समय धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। बेहद जरूरी है। मौसम के लगातार बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में नवतपा के दौरान गर्मी और अधिक प्रचंड रूप ले सकती है।

एक अरब 8 करोड़ की जलावर्धन योजना के तहत 36 वार्डों में पानी सप्लाई रहेगी बंद

एमपीईबी लाइन कनेक्शन कार्य के चलते 23 मई को पूरे नगर में नहीं होगी पेयजल आपूर्ति

दैनिक कारखाने का सफर। सारणी

नगर पालिका परिषद सारणी द्वारा करीब एक अरब 8 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना के माध्यम से नगर के 36 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसी योजना के तहत आवश्यक तकनीकी कार्य किए जाने के कारण 23 मई दिन शनिवार को पूरे नगर क्षेत्र में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.के. मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का संचालन कर

रही अनुबंधित कंपनी में लक्ष्मी इंजीनियरिंग प्रा. लि. द्वारा एमपीईबी से नई लाइन जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए नगर पालिका से अनुमति मांगी गई है। तकनीकी कार्य के दौरान जल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित रहेगी, जिसके चलते नगर पालिका क्षेत्र के सभी 36 वार्डों में एक दिन के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पूर्व से ही आवश्यकता पानी का संग्रह कर लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दिव्यांगों और वरिष्ठजनों के लिए राहत का शिविर अब जरूरतमंदों को मिलेगा सहायक उपकरण

22 मई को मंगल भवन सारणी में लगेगा एडिप एवं वयोश्री योजना का चिन्हांकन शिविर, पात्र हितग्राही उठाएं लाभ

दैनिक कारखाने का सफर। सारणी

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एडिप एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 22 मई शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मंगल भवन सारणी में चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का पंजीयन एवं आवश्यक उपकरणों के लिए चयन किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.के. मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक जिन्हें

चलने-फिरने, सुनने अथवा दैनिक जीवन में सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, वे शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में आने वाले हितग्राहियों को अपने साथ यूसीआईडी कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज की दो फोटो अनिवार्य रूप से लाना होगा। नगर पालिका प्रशासन ने क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन की जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

कांग्रेस दफतर में विचारधारा कम, कटआउट विज्ञान का शोध अधिक कार्यकर्ता पृष्ठ रहे हम पार्टी में हैं या किसी जमींदारी रियासत में



फ्लेक्स की फोटो बड़ी, संगठन की हालत खड़ी-खड़ी!

प्रमोद गुप्ता सारणी

मध्यप्रदेश की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प कथा है। वर्ष 2003 में सत्ता की चौखट से कांग्रेस ऐसी फ्लेक्स की फिकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 23 वर्षों तक सत्ता के खेत में ऐसी फसल बोई कि कांग्रेस की राजनीतिक नर्सरी में हरियाली उगने का नाम ही नहीं ले पाई। बीच में 17 माह की सरकार आई भी तो अपने ही लोगों ने घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत को जीवंत कर दिया। अब यही राजनीतिक रामलीला सारणी ब्लॉक कांग्रेस में मंचित होती दिखाई दे रही है। यहाँ कार्यकर्ता जैसे ही दुर्लभ हैं जैसे जून की दोपहर में टंडी हवा, लेकिन जो गिने-चुने लोग पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उनके साथ व्यवहार ऐसा किया जा रहा है मानो वे कार्यकर्ता नहीं, किसी जमींदारी के बंधुआ खेतियार हों। राजनीति में संगठन को परिवार कहा जाता है, लेकिन यहाँ हालात कुछ यूँ हैं कि बड़े साहब की कुर्सी के आसपास घूमने वालों की फोटो फ्लेक्स में बड़ी

हो जाए, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च आदर्श बन गया है। 10/15 के फ्लेक्स में किसका चेहरा ज्यादा चमके और किसका कोना कटे इस महामंथन विषय पर इतना मंथन हो रहा है कि लगता है मानो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही हो। उधर कार्यकर्ता सोच रहा है कि भैया बूथ संभालें या पोस्टर में अपनी गर्दन नापें। राजनीतिक धरातल पर पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता लगातार किनारा कर रहे हैं और कई तो कांग्रेस को प्रणाम कर घर बैठे अपने ही भलाई समझ रहे हैं। स्थिति यह है कि हिमाचली टोपी और लच्छेदार संवादों के सहारे संगठन चलाने वाले कुछ पदाधिकारी अब भी खुद को राजनीतिक जमींदार समझ बैठे हैं। मगर वक्त बदल चुका है। कार्यकर्ता अब केवल ताली बजाने वाला दर्शक नहीं रहा, वह सम्मान भी चाहता है और भागीदारी भी। पिछले विधानसभा चुनाव में कई बूथों पर कांग्रेस के पास बैठने तक कार्यकर्ता उपलब्ध

नहीं थे। यद्यपि यही फोटो पुरान और अहम महोत्सव चलता रहा, तो आने वाले नगरी निकाय चुनाव में बूथों पर कुर्तियां तो मिल जाएंगी, लेकिन उन पर बैठने वाले कार्यकर्ता शायद नहीं। कांग्रेस कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं का साझा आंगन है जिन्होंने वर्षों तक धूप, धूल और विरोध के बीच पार्टी का झंडा उठाए रखा। मगर यहाँ हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग संगठन को बरगद का पेड़ नहीं, निजी बाड़ी समझ बैठे हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा भी बैठने लगी है कि लंबे समय तक पीपल और बरगद की तरह पार्टी से चिपकी रहने वाली शाखाएं अब सूखकर टूट रही हैं। ऐसे में जिम्मेदार पदाधिकारियों को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर कार्यकर्ता दूर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि राजनीति में केवल भाषणों की मिठास नहीं चलती, कार्यकर्ताओं के सम्मान की भी खाद डालनी पड़ती है वरना संगठन का पौधा धीरे-धीरे सूखकर सिर्फ फ्लेक्स तक सीमित रह जाता है।